RNI Reg. No. CHHBIL/2020/80139
Volume- 04 Issue- 03
Bilingual Monthly (Hindi-English)

December 2023
Price- RS 20
32 Pages

Lok Shakti

लोक शक्ति

संसद स्प्रे कांड भारत को बदनाम करने की साजिश?

कई पोषक तत्वों से भरपूर है मूंगफली

मूंगफली सर्दियों में खानी भी चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है. यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है. कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होती है मूंगफली. आइए जानते हैं, पीनट्स यानी मूंगफली के फायदों के बारे में यहां.

प्रोटीन से भरपूर

प्रोटीन शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है. प्रोटीन एंजाइम्स, हार्मोन, ऊर्जा, ब्लड, स्किन, हेयर, नाखूनों, टिशूज आदि के निर्माण में इसकी जरूरत होती है. प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण में भी मदद करता है. लंबी उम्र तक अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखना है तो प्रोटीन से भरपूर मूंगफली का सेवन करें.

भूख करे नियंत्रण

मूंगफली में स्वस्थ मोनोअनसैचुरेटेड फैट का प्रकार एक हार्मोन को उत्तेजित कर सकता है, जो मूंगफली खाने के तुरंत बाद आपको संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है. ऐसे में मूंगफली खाते हैं तो आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा.

त्वचा को रखे हेल्दी

विटामिन बी3 और नियासिन से भरपूर होने के कारण मूंगफली झुर्रियों से मुक्त त्वचा को बढ़ावा देती है. ये सभी प्रकार के त्वचा रोगों को दूर रखती है. ऐसे में आप नियमित सीमित मात्रा में मूंगफली जरूर खाएं. इससे स्किन में निखार आएगी. सर्दियों में स्किन फटने लगती है, ऐसे में आप पीनट ऑयल अप्लाई करें.

मसल्स को मजबूती :

मूंगफली में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, जो मांसपेशियों को सपोर्ट करता है. मसल्स को मजबूती देता है. फिजिकल एक्टिविटी के बाद रिकवरी को बढ़ावा देता है और शारीरिक विकास में सुधार करता है. आप सर्दियों में सीमित मात्रा में मूंगफली का सेवन करके खुद को हेल्दी रख सकते हैं.

अल्जाइमर में मदद करे

मूंगफली में नियासिन, रेस्वेराट्रोल और विटामिन ई उच्च मात्रा में मौजूद होते हैं, जो अल्जाइमर और उम्र से संबंधित संज्ञानात्मक गिरावट या खराबी से बचाने में प्रभावशाली हैं. यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपको बुढ़ापा आने से पहले ही भूलने की समस्या शुरू हो जाए तो अलर्ट हो जाएं और पीनट को डाइट का हिस्सा बनाएं.

गर्भवती महिलाओं के लिए है बेस्ट

फोलेट एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो प्रेग्नेंसी के दौरान गर्भवती महिला के लिए बेहद जरूरी होता है. फोलेट मूंगफली में काफी होता है. खासकर फोलेट गर्भावस्था के दौरान न्यूरल ट्यूब दोष के जोखिम को कम करता है. मूंगफली फोलेट का एक अच्छा स्रोत है. ऐसे में आप प्रेग्नेंट हैं तो मूंगफली का सेवन जरूर करें.

Lok Shakti

EDITOR-IN-CHIEF Premendra Agrawal
EXECUTIVE EDITOR Rajesh Agrawal
MANAGING EDITOR Mr. Subhash
GROUP CREATIVE EDITOR Anjana
CHIEF ART DIRECTOR Deepika
FOREIGN EDITOR(US) Jamuna
CHIEF DESIGNER Vineeta Agrawal

RNI: CHHBIL/2020/80139

BUSINESS OFFICE

CHIEF EXECUTING OFFICER Satyabhama Agrawal
GENERAL MANAGER Vinod Agrawal
PUBLISHER Premendra Agrawal
MARKETING DIRECTOR Mr. Subhash
PHOTOGRAPHER Pawan Kumar
DIGITAL Tejas Agrawal
CHIEF PHOTO RESEARCHER Krisha

HEAD OFFICE

LOK SHAKTI, Agrasen Marg
Ramsagarpara, Raipur,
Chhattisgarh - 492001 (INDIA)
Whatsapp : 9926022174
e-mail: lokshakti.india@gmail.com

Printed and published by Premendra Agrawal
Editor: Premendra Agrawal.
Printed at Commercial Services
Agrasen Marg, Ramsagarpara, Raipur (CG).
Published from LOK SHAKTI, Agrasen Marg
Ramsagarpara, Raipur (CG).

YEAR : 04; ISSUE : 03
Published for the Month of December , 2023
Released on December, 2023

Total no. of pages 32, including Covers

SCAN AND SHARE

Read Lok Shakti on your smart phone instantly. Point your phone's scanner on the code above and align it in the frame. You will be guided instantly to www.lokshakti.in.

NAVIGATOR

05 COVER STORY
संसद स्प्रे कांड भारत को बदनाम करने की साजिश

05 देश की सुरक्षा और लोकतंत्र के मंदिर से खिलवाड़
09 देश में मोदी लहर कायम
10 सर्वे का दावा, 2024 में भी बीजेपी सरकार

12 राजस्थान विधानसभा चुनाव
13 'प्रचंड' और 'तेजस' का तेज बढ़ाएगा
15 पूर्वोत्तर में शांति के नए युग की शुरुआत
16 J&k Election
18 उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
19 यूपी नंबर वन
20 लाउडस्पीकर और खुले में
21 पूरे होंगे छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास
22 IT छापे में मिला नोटों का पहाड़
23 पूर्वी क्षेत्र
24 एआई
25 उड़ान योजना से 130 लाख से अधिक लाभान्वित
26 वीर जवान, देश के विकास की नींव
28 तमिलनाडु में बाढ़ से संकट
29 ईदगाह मस्जिद का सर्वे
30 देश की जैव-अर्थव्यवस्था की छलांग
31 Five Individual Centuries In 2023

Message from Executive Editor's

We welcome you to our monthly magazine! You will find contents from across sectors including Politics, Education, Health, Economics among others. We have a great emphasis on Opinions, News & Analysis along with hints and Events from across the globe.

We want our publication to be valuable for you so please, do share your feedback and suggestions to help us improve. We have signed you up for our monthly magazine in the hopes that you will find great value in its content. Lok Shakti's publication comes with promise of great growth and change.

With each passing year, Interests and taste change, economies and leadership rise and fall, children age and grow … in truth it sees perhaps the most change of all.

…The media is simply a tool, and it's our job to help you use it in the way that's right for you as well as for the country and the world.

Sincerely,
Rajesh Agrawal
Executive Editor

सम्पादकीय

संसद स्प्रे कांड भारत को बदनाम करने की साजिश

भारत में चौतरफा विकास से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। देशवासियों के दिल में उनकी पैठ लगातार गहरी होती जा रही है। इससे सबसे ज्यादा घबराहट में अमेरिका, चीन और भारत के विपक्षी दल हैं। दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और चीन भारत के विकास की रफ्तार को रोकने के लिए हर तरह की तिकड़म कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के सामने उनकी एक नहीं चल रही है। वहीं देश में लगातार अपना जनाधार खो रही कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां विदेशी शक्तियों के साथ हाथ मिलाकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। 13 दिसंबर को संसद में घुस आए दो वामपंथी युवकों की घटना भी इन्हीं लोगों की रची साजिश का हिस्सा हो सकती है। वे भारत को बदनाम कर पीएम मोदी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं जिससे चुनाव में उन्हें हराया जा सके। लेकिन यह उनका दिवास्वप्न ही होने वाला है क्योंकि मोदी तो जन-जन के दिलों पर राज करते हैं।

संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर 13 दिसंबर को लोकसभा में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब विजिटर्स गैलरी से 2 युवक अचानक नीचे कूद गए। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। युवक सदन की बेंच पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगे। इसी बीच उन्होंने जूते से निकालकर स्मोक बम स्प्रे किया, जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लगा। इससे पूरे सदन में भगदड़ मच गई और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। संसद पर हंगामा करने वालों का वामपंथ से जुड़ाव, घर से गुरिल्ला वारफेयर की किताबें मिलना और आंदोलनों में हिस्सा लेने के सबूत यह साबित करता है वे लिबरल इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका में रह रहे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने संसद पर हमले की धमकी दी थी और भारत को सौंपने के बजाय अमेरिका उसे अपना नागरिक बताकर उसकी ढाल बना हुआ है। यह साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसे यहां के लेफ्ट लिबरल का साथ मिला।

राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं कि "एक बात हमें समझ नहीं आ रही है। हम इस राजा (मोदी जी) पर 24 घंटा आक्रमण करते हैं। जनता इसके खिलाफ है। कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पर आक्रमण करते हैं ऐसा लगता है मतलब हम गलत जगह तीर मार रहे हैं।" अब इसे तो यही कहा जाएगा कि कांग्रेस के अंतिम चिराग का हौसला अद्भुत है। संसद में हुए स्प्रे कांड को इस हताशा में भी ढूंढा जा सकता है।

पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस और सत्ता से बाहर हुए विपक्षी दल देश में जिस तरह नफरत फैलाने की कोशिश की है उसी का परिणाम है कि पांच लोग अचानक बेरोजगारी और तानाशाही से पीड़ित होकर इतना बड़ा जोखिम उठा लें। इनकी समझदारी की भी दाद देनी चाहिए बीजेपी को बदनाम करने के लिए इन्होंने भाजपा सांसद से ही पास बनवाया और संसद के भीतर जा पहुंचे। मोहब्बत की दुकान से नफरत फैलाने की वजह से आज 42 साल की आंदोलनजीवी महिला सहित पांच लोग बेरोजगारी का हवाला देकर संसद के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच जाती है। सवाल यह भी है कि जब कोई आंदोलन में ही लगा रहेगा तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा और रोजगार कैसे मिलेगा।

देश की सुरक्षा और लोकतंत्र के मंदिर से खिलवाड़

देश के लोकतांत्रिक इतिहास के पन्नों पर 13 दिसंबर का दिन फिर काले अक्षरों में दर्ज हो गया है। जिस तरह 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को आंतकियों ने संसद पर हमला करके पूरे देश को झकझोर दिया था, उसी तरह दिग्भ्रमित उपद्रवियों ने लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगाकर पूरे देश में सनसनी पैदा कर दी। उपद्रवियों और उनके संरक्षकों ने बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लोकतांत्रिक तरीके से परास्त नहीं कर सकते तो अराजकता और आतंकवाद का सहारा लेकर देश के खिलाफ भी काम कर सकते हैं। साजिशकर्ताओं ने सुनियोजित तरीके से संसद में दो युवकों की घुसपैठ कराकर प्रधानमंत्री मोदी और देश की छवि को धुमिल करने की कोशिश की है। फिलहाल इस साजिश में शामिल पांच लोगों को गिरफ्तार कर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। लेकिन इस साजिश में बड़े-बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका जतायी जा रही है। वहीं सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के हमदर्द भी सामने आ चुके हैं।

संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के बचाव में उतरे विपक्षी सांसद

संसद में घुसपैठ के मामले में सरकार और सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं। लोकसभा सचिवालय ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में आठ कर्मियों को निलंबित कर दिया। निलंबित किए गए लोगों की पहचान रामपाल, अरविंद, वीर दास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित और नरेन्द्र के रूप में की गई है। इस घटना में शामिल लोगों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा रही है। सरकार की सख्ती देख अब संसद में सेंध लगाने वालों के हमदर्द भी सामने आने लगे हैं। विपक्ष के सांसद संसद की गरिमा को तार-तार करने वालों को पीड़ित के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्हें बेरोजगार और भ्रमित युवा बता रहे हैं। यहां तक कि सख्त कार्रवाई नहीं करने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आरजेडी सांसद शिवानंद तिवारी ने कहा कि हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई दंड है कि उस पर कोई कार्रवाई किया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील रिंकू ने कहा कि उनके ऊपर इस तरह की सख्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हैं तो अपने देश के नागरिक ही। देश के लोग ही हैं। उनका तरीका गलत हो सकता है लेकिन मकसद गलत नहीं था।

देश और मोदी सरकार की छवि धुमिल करने की कोशिश - दरअसल 13 दिसंबर, 2023 को शून्यकाल के दौरान संसद में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो घुसपैठिए सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए। ये घटना दोपहर डेढ़ बजे के करीब हुई। सदन में कार्यवाही चल रही थी। तभी अचानक दो लोग सांसदों के बीच कूद गए। उन्होंने कलर स्मॉग का इस्तेमाल किया, जिससे सांसदों में के बीच अफरा-तफरी मच गई। सांसदों ने आरोपियों को पकड़ा और उनकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद उन्हें सदन में मौजूद मार्शल के हवाले किया गया। सदन में कूदने वालों की पहचान सागर और मनोरंजन डी के रूप में हुई है। सागर उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। वहीं, संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किए गए दो लोगों की पहचान हरियाणा के जींद जिले के गांव घासो खुर्द निवासी नीलम और महाराष्ट्र के लातूर निवासी अमोल शिंदे

के रूप में हुई है।

घटना को अंजाम देने के लिए संसद भवन की दो बार की गई थी रेकी

नीलम और अमोल शिंदे ने संसद भवन के बाहर कलर स्मॉग का इस्तेमाल किया और नारेबाजी की। इसके बाद बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ललित और विशाल शर्मा के रूप में दो अन्य आरोपी भी इस साजिश में शामिल थे। विशाल को हरियाणा के गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया, जबकि ललित फिलहाल फरार है। संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के बारे में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज 'भगत सिंह फैन क्लब' से जुड़े थे। यह सभी आरोपी करीब डेढ़ साल पहले एक दूसरे से मैसूर में मिले थे। लगभग नौ माह पहले वे फिर मिले और अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए संसद का उपयोग करने का निर्णय लिया। घटना को अंजाम देने के लिए संसद भवन की दो बार रेकी की गई थी। सागर और मनोरंजन ने इस साल मार्च और जुलाई महीने में संसद की रेकी की थी। इन्हें पहली बार में ही बड़ी सफलता मिल गई थी, जबकि दूसरी बार में उन्हें मायूसी हाथ लगी थी।

संसद में घुसपैठ के लिए
डेढ़ साल पहले से की जा रही थी साजिश

संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने से पहले 10 दिसंबर की रात में सागर, नीलम और अमोल गुड़गांव में विक्की (मनोरंजन का दोस्त) के घर पहुंचे। विक्की शर्मा गुड़गांव के सेक्टर- 7 में मकान नंबर 67 में एक एक मंजिला इमारत में रहता है। रात में ललित आया और अगली सुबह मनोरंजन फ्लाइट से आया। सागर, अमोल, ललित और मनोरंजन की यही पहले मुलाकात हुई थी। वे संसद में आगंतुकों के लिए पास की व्यवस्था करने के लिए तीन रात और दो दिन गुड़गांव में रुके। योजना के तहत 14 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करना था, लेकिन उन्हें पहले ही पास मिल गया। उन्होंने एक दिन पहले 13 दिसंबर को ही विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। स्मॉग बम का जुगाड़ पहले ही कर लिया गया था। अमोल ने स्मॉग बम को लातूर में खरीदा था जिसे बाद में सागर ने कुर्ला से एकत्रित किया था। सागर ने जूते खरीदे और स्थानीय मोची की मदद से उन जूतों में छेद कराया और उसे बंद करवा दिया।

सुनियोजित तरीके से दिया गया घटना को अंजाम

साजिश में शामिल पांच लोगों ने 13 दिसंबर को इंडिया गेट पर करीब आधे घंटे तक मीटिंग की। इस दौरान तय हुआ कि सागर और मनोरंजन संसद में प्रवेश करेंगे और दोनों को पीले रंग का एक-एक स्मॉग (धुआं) बम दिया गया, जिसे उन्होंने अपने जूतों के अंदर छिपाया। सागर ने जूतों में कुछ पर्चे भी छिपा रखे थे। चूंकि स्मॉग बम फेंकने के बाद उन्हें पर्चे फेंकने थे। जबकि नीलम, अमोल और ललित झा को संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करना था। दोपहर करीब 12 बजे सागर और मनोरंजन संसद में घुसे और संसद में स्मॉग बम फेंक दिया। वहीं संसद के बाहर नीलम और अमोल शिंदे ने कलर स्मॉग का इस्तेमाल किया और नारेबाजी की। जब पुलिस ने नीलम को पकड़ा तो वो हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भीम, तानाशाही बंद करो, लोकतंत्र बचाओ-संविधान बचाओ के नारे लगा रही थीं।

नीलम फिलहाल पुलिस के हिरासत में है। लेकिन उसके बारे में हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले मई में नीलम को दिल्ली में महिला पहलवानों के आंदोलन के दौरान हिरासत में लिया गया था। नीलम ने किसानों के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और हरियाणा में कई विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा रही थीं। 2020 में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसानों के आंदोलन में नीलम काफी सक्रिय थीं। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए दिल्ली कूच कर रहे पंजाब के किसानों का नीलम ने 26 नवंबर, 2020 और उसके बाद हरियाणा में प्रवेश करने पर उचाना कलां शहर में स्वागत किया था। इसी साल जब बीजेपी सांसद और तत्कालीन कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रज भूषण शरण सिंह के खिलाफ जब महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर मई विरोध-प्रदर्शन किया था, तब भी नीलम उसमें शामिल थीं। दिल्ली पुलिस ने 28 मई को हिरास्त में लिया था।

लोकसभा में दो युवक विजिटर गैलरी से कूदे और स्मोक बम से पीले रंग का धुआं उड़ाने लगे। सुरक्षा में सेंध लगाने वाले दोनों लोगों को पहले सांसदों ने पीटा, फिर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस सिक्योरिटी ब्रेक के 6 किरदार सामने आए हैं। दो ने सदन के अंदर हंगामा किया, दो ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। ये चारों पुलिस की गिरफ्त में हैं। दो और लोग प्लानिंग में शामिल थे, इनमें से एक ने सभी को अपने घर में ठहराया था। उसे पुलिस ने पत्नी समेत हिरासत में ले लिया है। हालांकि, पत्नी इन छह आरोपियों में शामिल नहीं है। एक अभी भी फरार है।

संसद में पहुंचकर और संसद के बाहर हंगामा करने वाले छह किरदारों पर एक नजर-

नीलम आजादः हिसार के PG में रहकर HTET की पढ़ाई कर रही थी

नीलम आजाद के फेसबुक प्रोफाइल से पता चलता है कि वो आंदोलनजीवी है। उसे पहले भी कई विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय देखा गया है। जिस समय सागर और मनोरंजन लोकसभा में हंगामा कर रहे थे, उसी वक्त अमोल और नीलम संसद के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे थे। नीलम हरियाणा के जींद जिले के घसो खुर्द गांव की रहने वाली है। पिछले 6 महीने से हिसार में पेइंग गेस्ट (PG) में रहकर हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम और HTET (हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा) की तैयारी कर रही थी। नीलम का राजनीति में इंट्रेस्ट था और वह किसान आंदोलन से लेकर पहलवान आंदोलन के साथ कई अन्य आंदोलनों में हिस्सा ले चुकी है। पहलवान आंदोलन के दौरान पीटी उषा के साथ धक्का मुक्की करने वाली प्रदर्शनकारियों में नीलम भी शामिल थी। नीलम के छोटे भाई राम निवास ने कहा- हमें तो पता ही नहीं था कि वह दिल्ली गई है। वह सोमवार को आई थी, इसके बाद मंगलवार को वापस चली गई। हमें तो यही लगा था कि वह हिसार जा रही है। उसने कई बार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। वह किसान आंदोलन में भी गई थी। परिवार में मेरा बड़ा भाई और माता-पिता हैं। पिता हलवाई हैं, जबकि मैं और मेरा भाई दूध का काम करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा इनके समर्थन में उतर आया है और रिहाई की मांग की है।

सागर शर्माः लखनऊ में चलाता है ई-रिक्शा, पिता कारपेंटर

संसद की विजिटर्स गैलरी में कूदने वाले दो युवकों में से एक सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है। सागर का परिवार लखनऊ के आलमबाग के रामनगर में किराए के घर में रहता है। पिछले 15 सालों से सागर का परिवार लखनऊ में रह रहा है। पिता रोशनलाल कारपेंटर हैं। वह खुद लखनऊ में ई-रिक्शा चलाता है। सागर सोशल मीडिया पोस्ट को देखें तो पता चलता है कि वह रवीश कुमार को फॉलो करता है। गौमूत्र से गरारा करने वाले बोलकर सनातन पर हमला करता है और मोदी-शाह के खिलाफ जहर उगलता है। सागर की मां रानी शर्मा ने कहा कि बेटा धरना-प्रदर्शन करने की बात कहकर घर से गया था। सागर की छोटी बहन ने कहा कि भाई चार दिन पहले दिल्ली गया था। वह दो महीने पहले बेंगलुरु से लौटा था। सागर की मां ने कहा, बेटा बहुत सीधा है, पता नहीं कैसे दिल्ली पहुंच गया।

मनोरंजन गौराः पेशे से इंजीनियर, घर से गुरिल्ला वारफेयर की किताबें मिली

संसद की विजिटर्स गैलरी में कूदने वाले डी मनोरंजन दूसरा युवक है। वह कर्नाटक के मैसुरु का रहने वाला है। उसने 2016 में बैचलर इन इंजीनियरिंग (BE) की पढ़ाई पूरी की थी। दिल्ली और बेंगलुरु में कुछ कंपनियों में काम भी किया। अब वह परिवार के साथ खेती का काम देख रहा था। मनोरंजन ने भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस से लोकसभा में एंट्री के लिए पास लिया था। उसने सागर शर्मा को अपना दोस्त बताया था। उसके घर से गुरिल्ला वारफेयर सहित भारी मात्रा में वामपंथी किताबें मिली है। मनोरंजन के पिता देवराजे गौड़ा ने कहा कि अगर मेरे बेटे ने गलत किया है, तो उसे फांसी पर लटका दीजिए। हालांकि, उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका बेटा ईमानदार और सच्चा है। उसकी एकमात्र इच्छा समाज के लिए अच्छा करना और समाज के लिए बलिदान देना है।

अमोल शिंदे: सेना भर्ती में जाने की कहकर घर से निकला था

अमोल शिंदे (25) महाराष्ट्र के लातुर जिले के जरी गांव का रहने वाला है। उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। वह पुलिस और सेना भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के साथ दिहाड़ी मजदूरी करता था। अमोल के मां-बाप और दो भाई भी मजदूरी करते हैं। अमोल के परिवार के मुताबिक, वह 9 दिसंबर को यह कहकर घर से निकला था कि वह सेना भर्ती के लिए दिल्ली जा रहा है। उसने पहले भी इस तरह के कई भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था, इसलिए उसके माता-पिता को कोई शक नहीं हुआ।

विक्की शर्मा: गुरुग्राम के विक्की के घर रुके थे सभी आरोपी

संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने वाले सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल शिंदे दिल्ली जाने से पहले गुरुग्राम में रुके थे। इनके साथ ललित झा भी था। यह लोग गुरुग्राम के सेक्टर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले विक्की के घर रुके थे। विक्की शर्मा मूल रूप से हरियाणा के हिसार का रहने वाला है। यहीं के PG में संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली नीलम पिछले 6 महीने से रह रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों की टीम ने विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये चारों विक्की शर्मा के दोस्त हैं। इसके बाद शक जताया जा रहा है कि संसद भवन के बाहर प्रदर्शन और अंदर धुआं फैलाने की पूरी साजिश यहीं तो नहीं रची गई। जब आरोपी यहीं से दिल्ली गए तो फिर क्या उनके मोबाइल यहीं रखे गए थे।

ललित झा: स्प्रे कांड का मास्टरमाइंड फरार, कांग्रेस से कनेक्शन!

ललित झा अभी फरार चल रहा है। घटना के वक्त ललित भी संसद परिसर में ही मौजूद था। जैसे ही हंगामा शुरू हुआ आरोपी ललित वहां से भाग गया। ललित के पश्चिम बंगाल कांग्रेस कार्यालय में फोटो से साफ होता है कि उसका कांग्रेस से जुड़ाव है। ललित झा को संसद में घुसपैठ का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ललित बिहार का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक है। ललित को कोलकाता में कई सामाजिक समारोहों में देखा गया था। उसके कई एनजीओ से जुड़े होने की बात भी सामने आई है। इनमें ज्यादातर बंगाल के एनजीओ हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ललित झा फरार होने से पहले अपने एनजीओ पार्टनर नीलाक्ष आइच को संसद में घुसपैठ का एक वीडियो व्हाट्सएप पर भेजा था।

संसद में तो अपने ही लोग गए, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया

अभी पूरा विपक्ष शोर मचा रहा है, संसद पर हमला हो गया, एक्शन लो एक्शन लो। यह सुरक्षा मे बहुत बड़ी चूक हुई है और जो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब एक्शन हो रहा है और आरोपियों पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इसे लेकर विपक्ष और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में रोना धोना शुरू हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो नीलम की रिहाई की मांग की है तो एक वामपंथी विश्लेषक कह रहे हैं- "संसद में तो अपने ही लोग गए हैं, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, विरोध करने गए थे ना भाई।" इस स्तब्धकारी घटना ने बौद्धिक अलगववाद और बौद्धिक आतंकवाद को पोषित करते एक बड़े सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर वर्ग को भी निःसंदेह रूप से आमजनमानस के सामने नंगा किया है।

हार की पटकथा लिखते रहे, भारी पड़ी मोदी की गारंटी

दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठकर जब स्वयंभू राजनीतिक पंडित राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की हार की पटकथा लिख रहे थे तब उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि मतदान बूथों पर इन प्रदेशों की महिलाएं, गरीब और मजदूर अपने मतों के प्रयोग से पूरी पटकथा का क्लाइमेक्स छाप रहे थे। क्लाइमेक्स था, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है।

प्रधानमंत्री के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर जनता ने मुहर लगा दी। जिन राजनीतिक पंडितों को चुनाव से पहले यह बात समझ नहीं आ रही थी, वे भी नतीजों के बाद इसके विश्लेषण में लग गए। चुनाव नतीजों के यही निहितार्थ हैं कि तीनों राज्यों की महिलाएं, गरीब, किसान और युवा पीढ़ी ने पीएम मोदी की गारंटी पर पूरा विश्वास जताया है। यह जीत मोदी की गारंटी की जीत है। इन परिणामों में लोकसभा चुनाव के लिए दूरगामी संदेश निहित है, जिसे विपक्षी दल बखूबी समझ रहे हैं। इस कारण कांग्रेस के सहयोगी दलों में बेचैनी साफ दिख रही है। अब यह कोई प्रश्न ही नहीं बचा कि हिंदी पट्टी में सबसे लोकप्रिय पार्टी कौन है? पिछले नौ वर्षों में भारतीय राजनीति में मोदी नाम भरोसे और विश्वास की गारंटी बन गया है। किसी गारंटी के साथ मोदी का नाम जुड़ जाए तो जनता उस पर पूरा भरोसा करती है। यह विश्वास चुनाव परिणामों में दिख रहा है।

देश में मोदी लहर कायम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की जनता के दिलों में बसते हैं। जनता पर उनका ना सिर्फ भरोसा बरकरार है, बल्कि इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साढ़े नौ साल से केंद्र की सत्ता में रहने के बावजूद जनता पर प्रधानमंत्री मोदी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने खूब लोकलुभावन वादे किए और रेवड़ियां बांटी। इसके बावजूद तीन राज्यों में प्रचंड बहुमत और तेलंगाना में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन ने फिर साबित कर दिया है कि देश में मोदी लहर कायम है। इस लहर ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया कर दिया है। वहीं तेलंगाना में बीजेपी एक से बढ़कर आठ सीटों तक पहुंच गई है। इस शानदार जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने सर झुकाकर अभिवादन किया।

चुनाव आयोग के शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के 230 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 48.64 प्रतिशत वोट के साथ 163 सीटें पर आगे चल रही है या जीत चुकी है। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी के वोट शेयर में करीब सात प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 230 सीटों में से बीजेपी को 109 सीटें मिली थीं। बीजेपी का वोट शेयर 41.02 प्रतिशत था।

राजस्थान में 41.71 प्रतिशत वोट के साथ 115 सीटें - चुनाव आयोग के शाम 6 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान के 200 सीटों के लिए हुए चुनाव में वोट शेयर में करीब तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें, बीजेपी को 73 सीटें, बीएसपी को 6 सीटें, सीपीएम को 2 सीटें और अन्य को 19 सीटें मिली थीं। बीजेपी का वोट शेयर 38.77 प्रतिशत, कांग्रेस का वोट शेयर 39.30 प्रतिशत और बीएसपी का वोट शेयर 4.03 प्रतिशत था।

छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 46.30 प्रतिशत वोट के साथ 54 सीटें - निर्वाचन आयोग के शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 90 सीटों के लिए हुए चुनाव में फिलहाल बीजेपी 46.30 प्रतिशत वोट के साथ 54 सीटें जीत चुकी है या आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है। साल 2018 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुल 90 सीटों में से कांग्रेस को 68, बीजेपी को 15, अन्य को 7 सीटें मिली थीं। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 43.04 प्रतिशत था। बीजेपी का वोट प्रतिशत 32.97 प्रतिशत था।

तेलंगाना में 14 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 8 सीटें
दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में बीजेपी इस बार पहले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है। बीजेपी फिलहाल करीब 14 प्रतिशत वोट शेयर के साथ आठ सीटों पर जीत दर्ज की है। अगर पिछले चुनाव से तुलना करें तो अब भी उसके प्रदर्शन को शानदार ही कहा जाएगा। पिछले चुनाव में जहां पार्टी को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा था तो वहीं साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 6.98 प्रतिशत के साथ सिर्फ एक सीट हासिल की थी।

सर्वे का दावा, 2024 में भी बीजेपी सरकार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता देश भर में लोगों के सर चढ़कर बोलती है। चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव या फिर स्थानीय निकाय चुनाव देश में मोदी लहर कायम है। बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतती जा रही है। ईटीजी रिसर्च के साथ टाइम्स नाउ नवभारत सर्वे में दावा किया गया कि 2024 में भी एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। विपक्षी एकता की ताजा मुहिम के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर Times Now Navbharat और ETG Research के सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। सर्वे के अनुसार अभी चुनाव हुए तो 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 296 से 326 सीटें मिल सकती हैं यानी बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A. को 160 से 190 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे से साफ है कि तमाम कोशिशों को बावजूद विपक्ष मोदी सरकार को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है।

विदेशी निवेशकों को भी भरोसा, 2024 में फिर बनेगी मोदी सरकार

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत की साख दुनिया भर में मजबूत हुई है। मोदी सरकार बनने के बाद एफडीआई नीति में सुधार, निवेश के लिए बेहतर माहौल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कदम उठाने का परिणाम है कि वे वैश्विक मंदी काल में भी विदेशी निवेशक भारत में जमकर निवेश कर रहे हैं। देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार होने के कारण दुनिया भर के निवेशकों को लगता है कि भारत में उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। इसी भरोसे में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) लगातार भारत में निवेश कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में एक बार फिर मोदी सरकार सत्ता संभालेगी।

यूबीएस सिक्योरिटीज ने एक अध्ययन में कहा है कि ज्यादातर वैश्विक निवेशकों ने नरेन्द्र मोदी की जीत पर दांव लगाया है। स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज ने 50 से अधिक अमेरिकी और यूरोपीय निवेशकों के साथ बैठक कर यह रिपोर्ट तैयार की है। इन निवेशकों ने दिसंबर तिमाही में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों को नजरअंदाज कर दिया है। इनका मामना है कि सप्लाई चेन के स्थानांतरित होने से भारत एक प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभर सकता है। दुनिया मानकर चल रही है कि वैश्विक संकट काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से साथ खड़ी है। इन निवेशकों को पूरा विश्वास है कि भारत में एक बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है। इसलिए वे इस वैश्विक मंदी काल में भारत को एक प्रमुख निवेश स्थल के रूप में देख रहे हैं।

अमेरिकी मीडिया का दावा- 2024 में भी एक बार फिर बीजेपी सरकार

बीजेपी की जीत की गूंज सात समंदर पार अमेरिकी मीडिया में भी सुनाई देने लगी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने साफ कहा है कि भारत में मोदी लहर कायम है और 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की तारीफ करते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी बताया है। अखबार ने लिखा है कि 2014, 2019 की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी 2024 में भी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। और आने वाले समय में पार्टी और तेजी से आगे बढ़ेगी।

वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार हाल ही में बीजेपी को ईसाई बहुल पूर्वोत्तर में बड़ी कामयाबी मिली है। साथ ही 20 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिया मुसलमानों का मजबूत समर्थन प्राप्त है। India's BJP Is the World's Most Important Party टाइटल से छपे आर्टिकल के अनुसार अमेरिकी दृष्टिकोण से भी बीजेपी सबसे महत्वपूर्ण विदेशी पार्टी है, लेकिन इसे कम समझा गया है। अखबार ने इसके साथ ही ये भी लिखा है कि इस समय भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और अमेरिका भारत की मदद के बिना चीन से मुकाबला नहीं कर सकता है।

जनमत पोल्स सर्वे का दावा अभी चुनाव हुए तो फिर मोदी सरकार

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत का कांग्रेस को कोई खास फायदा नहीं मिलता दिख रहा है और अगर देश में अभी लोकसभा चुनाव हो तो एक बार फिर मोदी सरकार बनती दिख रही है। जनमत पोल्स के ताजा सर्वे में दावा किया गया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का लोकसभा चुनाव का नहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ठीक बाद किए गए इस सर्वे में कहा गया है कि अभी लोकसभा चुनाव होने पर बीजेपी को 290-293 सीटें मिल सकती हैं। जबकि कांग्रेस को सिर्फ 62-64 सीटों पर ही संतोष करना होगा। इस सर्वे से साफ है कि देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता कायम है और आगामी लोकसभा चुनाव में भी उनके नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।

महिलाओं के विश्वास पर हासिल जीत

- स्मृति ईरानी का विशेष लेख

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक आलेख लिखा है। इस विशेष लेख में स्मृति ईरानी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी पर महिलाओं का अटूट विश्वास भारतीय राजनीति का नया अध्याय लिख रहा है। आवास योजना, उज्जवला योजना जैसी सफल नीतियों के बाद केंद्र सरकार ने हाल ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम सदन में पारित किया है। उन्होंने लिखा है कि नारी शक्ति का विकास भाजपा के विकास मॉडल का मुख्य आधार है।

2024 के ग्रांड फिनाले से पहले 4 राज्यों में मिली बड़ी विजय में किंग-मेकर की भूमिका महिला मतदाताओं ने निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर उनका अटूट विश्वास भारतीय राजनीति का नया अध्याय लिख रहा है, जहां महिलाओं को वोटरों के तौर पर बड़ी संगठित शक्ति के तौर पर देखा जाने लगा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 21वीं सदी के अति-आधुनिक दौर और महिला सशक्तीकरण की तमाम चर्चाओं के बीच किसी ने सोचा नहीं था कि महिलाओं का संगठित वोट इतने बड़े स्तर पर राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकता है।

शायद ही किसी तथाकथित विशेषज्ञ ने यह अनुमान लगाया होगा कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिला वोटरों के बीच भाजपा और मोदी के नेतृत्व के प्रति इतना समर्पण देखने को मिल सकता है। शायद यही वजह रही है कि अब तक महिलाओं को एग्जिट पोल में भी इतना अहम वोटर-सेग्मेंट नहीं माना गया था। पर सारे एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए। 3 दिसंबर 2023 को जारी हुए 4 राज्यों के चुनाव-परिणामों ने सारी वर्जनाओं को तोड़ डाला है।

आवास योजना, उज्जवला योजना जैसी सफल नीतियों के बाद केंद्र सरकार ने हाल ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम सदन में पारित किया था। साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं के ऐलान और मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना को लागू करके एक उदाहरण पेश करने से लेकर महिलाओं से जुड़े मसलों को चुनावी मुद्दे बनाने का पूरा लाभ भाजपा को मिला है।

राजस्थान में 48 प्रतिशत महिला वोटरों ने कांग्रेस के खिलाफ फैसला सुनाते हुए मोदी और भाजपा पर अपना भरोसा जताया। राजस्थान की 88 सीटों पर महिला वोटर पुरुषों की तुलना में अधिक हैं और इनमें से 55 पर भाजपा ने अपना परचम लहराया है। इसके अलावा अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 8 सीटें जीती हैं।

मध्य प्रदेश की बात करें तो अपने संकल्पों की सिद्धि के साथ ही मोदी ने खूब जोर-शोर से चुनाव-प्रचार किया। उन्होंने मतदाताओं तक पहुंचने के लिए कुल 14 रैलियां और रोड शो किए। किसान, महिलाएं, आदिवासी हों या फिर गरीब तबका, हर वर्ग तक वे पहुंचे।

सात फीसदी भाजपा मतदाताओं ने मोदी फैक्टर की वजह से भाजपा को वोट किया। आंकड़ों से यह भी साफ है कि इस बार ग्रामीण वोटरों में भी महिला वोटरों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक थी, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिला है।

मध्य प्रदेश में 'एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी' की भाजपा की थीम चरितार्थ होती दिखी। लोगों का कहना है कि मोदी का नाम ही मतदाताओं में विश्वसनीयता, सम्मान और अपनेपन की भावना लेकर आता है, जिसने भाजपा की जीत पर मुहर लगा दी।

कुछ ऐसा ही भाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। वहां पार्टी के जमीनी प्रचार कार्यों ने बेहतरीन माइक्रो-मैनेजमेंट का परिचय देते हुए आदिवासी महिलाओं तक भाजपा द्वारा महिलाओं के हित में चलाए जाने वाली योजनाएं पहुंचाईं। मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए खुद प्रधानमंत्री ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रचंड जीत के बाद संबोधित करते हुए कहा, 'मैं देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा।

नारी शक्ति ये ठानकर निकली है कि वो भाजपा का परचम लहराएगी। नारी शक्ति का विकास भाजपा के विकास मॉडल का मुख्य आधार है। इसलिए इन चुनावों में महिलाओं, बहनों-बेटियों ने भाजपा को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। मैं पूरी विनम्रता से देश की हर बहन-बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वादे भाजपा ने किए हैं, वो शत-प्रतिशत पूरे किए जाएंगे और ये मोदी की गारंटी है।'

ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने महिला वोटरों को लुभाने के प्रयास नहीं किए। कर्नाटक चुनाव के समय से ही कांग्रेस ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली स्कीम पर जोर दिया, जिसका उसे कर्नाटक में फायदा भी मिला। परिणामस्वरूप, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं को चुनावी प्रचार में बल मिला और मध्य प्रदेश में उज्जवला योजना, आवास योजना, महिलाओं को नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण, संपत्ति खरीद पर मिलने वाली छूट और अंततः लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन ने एवं अन्य राज्यों में ऐसी ही घोषणाएं करके एक राज्य में उन्हें चुनाव से पहले ही लागू करने की नीति ने भाजपा को 'एक्शन मोड' वाली पार्टी की श्रेणी में रख दिया था, जिसकी काट कांग्रेस निकालने

राजस्थान विधानसभा चुनाव: बदला राज, नहीं बदला रिवाज

कांग्रेस चुनाव के कुछ महीने पहले तक गुटबाजी से ही जूझती नजर आई। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खींचतान का भी कार्यकर्ताओं पर असर पड़ा। न सिर्फ जनता के बीच गलत संदेश गया, बल्कि प्रदेश के विकास कार्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। कांग्रेस जहां गुटबाजी से जूझती रही, वहीं बीजेपी ने अंतर्कलह को कहीं बेहतर तरीके से हैंडल किया। सीएम फेस का ऐलान दोनों ही दलों ने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की ओर से सीएम अशोक गहलोत ही अघोषित सीएम फेस थे। वहीं, बीजेपी ने रणनीति के तहत बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया। इन नेताओं ने अपनी साख बचाने के लिए उस सीट पर जोर लगाया और बीजेपी के लिए इसका सकारात्मक असर आसपास की सीटों पर भी पड़ा।

राजस्थान में अशोक गहलोत को भले ही जादूगर कहा जाता हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो पीएम मोदी का जादू जनता-जनार्दन से सिर पर चढ़कर बोला है। सीएम चेहरा घोषित न करने की बीजेपी थिंक टैंक की रणनीति ने सफलता के झंडे गाड़ दिए और चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा बने पीएम नरेन्द्र मोदी पर ही मतदाताओं ने अपना स्नेह और आशीर्वाद जीभर लुटाया। जनता की लहर ने RAJsthan को MODIsthan बना दिया। प्रदेश की जनता ने गहलोत सरकार द्वारा घोषित की गई मुफ्त की रेवड़ियों/गारंटियों को पूरी तरह नकार दिया और उसने मोदी की गारंटी पर ही जमकर भरोसा किया। प्रदेश में पीएम मोदी की धुआंधार रेलियों और उसमें उठाए शानदार और दमदार मुद्दों ने सरकार के खिलाफ और बीजेपी की पक्ष में लहर बनाई। पीएम मोदी की ऐसी सुनामी चली कि राजस्थान के साथ-साथ छत्तीसगढ़ भी बीजेपी को बोनस में मिला और पड़ौसी मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की रिकॉर्ड जीत हुई।

पीएम मोदी की दमदार सभाओं ने बनाया बीजेपी के लिए जीत का रास्ता

पीएम मोदी ने इस चुनावी साल में राजस्थान में बीस से ज्यादा बड़ी सभाएं कीं। इसमें न सिर्फ उन्होंने संभाग और जिले को कनेक्ट किया, बल्कि राज्य की 200 विधानसभा क्षेत्रों को भी कवर किया। इन जनसभाओं में पीएम ने न सिर्फ कांग्रेस सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार की पोल खोली, बल्कि महिलाओं और अपराधों में राजस्थान को नंबर वन बनाने के लिए कांग्रेस की गहलोत सरकार पर निशाने साधे। पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ पीएम ने कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण की नीति को भी आड़े हाथों लिया। महिलाओं और युवाओं में खासे लोकप्रिय पीएम मोदी ने राजस्थान के दौरों के दौरान प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों और विभिन्न समाजों के आराध्य स्थलों पर भी दर्शन-पूजन किया। लोगों की धार्मिक भावनाएं पीएम मोदी के साथ जुड़ने का खासा असर चुनाव परिणामों पर नजर आया।गहलोत वर्सेज पायलट का अनवरत विवाद प्रदेश के विकास कार्यों पर हावी रहा

राजस्थान में तीन दशक से सत्ता को बदलने का रिवाज है। गहलोत सरकार ने इस रिवाज को बदलने और अपनी सत्ता में वापसी के लिए विज्ञापनों पर पैसा पानी की तरह बहाया था। लोगों को मुफ्त की योजनाओं के साथ-साथ सात गारंटियां भी दीं, लेकिन राजस्थान की जनता पिछले पांच साल में कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार के तंग आ चुकी थी। गहलोत वर्सेज पायलट का अनवरत विवाद प्रदेश के विकास कार्यों पर हावी रहा। इस पर विधायकों से लेकर मंत्रियों तक पर भ्रष्टाचार के आरोप, मंत्री पुत्रों पर रेप करने के आरोप, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और इस पर मुख्यमंत्री से लेकर शहरी

‘प्रचंड’ और ‘तेजस’ का तेज बढ़ाएगा भारतीय सशस्त्र सेनाओं की ताकत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक ओर आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नित-नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर सामरिक क्षेत्र में उनके विजन और सेना को दिये जा रहे हौसले से सरहदें और ज्यादा सुरक्षित हो रही हैं। वरना एक दशक पहले यूपीए सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तब आलम यह था कि सालों तक सैन्य क्षेत्र के सौदे और रक्षा समझौते ही ताक पर रख दिए गए थे। सेना के आधुनिकीकरण की बात तो दूर, सेना के इस्तेमाल के लिए खरीददारी भी भारी पड़ती नजर आती थी। जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली है, तो साफ कर दिया है कि अब एक मजबूत रक्षा कवच रहेगा और एक मजबूत सेना आत्मविश्वास से भरे भारत का प्रतीक होगी। पीएम मोदी न सिर्फ सेना के आधुनिकीकरण के लिए बल्कि सुधारों पर भी फोकस कर रहे हैं। आज भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसके पास अति आधुनिक हथियार हैं। चीन और पाकिस्तान से सटे मोर्चों पर दोहरी सामरिक चुनौती के मद्देनजर रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इसमें से 2.20 लाख करोड़ रुपए की खरीद स्वदेशी कंपनियों से होगी।हल्के लड़ाकू विमान तेजस एमके-1ए और प्रचंड हेलिकॉप्टर की होगी खरीद

पीएम मोदी ने तमाम रक्षा दलालों और कंपनी के स्तर पर चर्चा छोड़ कर सीधे फ्रांस सरकार के स्तर पर बातचीत कर राफेल की खरीद की राह प्रशस्त की थी। साथ ही मेक इन इंडिया को बढावा देने के लिए इसके कल पूर्जे भारत में बनाने का समझौता भी कराया। राफेल और लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट तेजस ने भारतीय वायुसेना की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में वायुसेना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से 97 हल्के लड़ाकू विमान तेजस एमके-1ए की खरीद को मंजूरी दी गई। एचएएल से सेना और वायुसेना के लिए 156 हल्के लड़ाकू हेलिकॉप्टर प्रचंड के खरीद प्रस्ताव भी मंजूर किए गए। इनमें से 90 प्रचंड हेलिकॉप्टर थलसेना, जबकि 66 वायुसेना के लिए खरीदे जाने हैं। एचएएल से स्वदेशी तौर पर सुखोई-30 एमकेआइ विमान के उन्नयन के लिए उपकरण खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई।

सेना को अत्याधुनिक बनाने को कई तरह के साजो-सामान की खरीद को मंजूरी

थल सेना के तोपखाना में अब सेवा अवधि पूरी कर चुकी इंडियन फील्ड गन (आइएफजी) की जगह टोव्ड गन सिस्टम लेगा। परिषद की बैठक में टीडीएस के खरीद प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

इसके अलावा 155 मिमी आर्टिलरी गन में उपयोग के लिए 155 मिमी नबलेस प्रोजेक्टाइल को मंजूरी दी गई। यह प्रोजेक्टाइल की मारक क्षमता और सुरक्षा बढ़ाएगा। टी-90 टैंकों के लिए स्वचालित लक्ष्य ट्रैकर और डिजिटल बेसाल्टिक कंप्यूटर तथा टैंक व बख्तरबंद गाडियों पर दुश्मन का वार बेअसर करने के लिए एंटी-टैंक युद्ध सामग्री, एरिया डेनियल म्यूनिशन (एडीएम) टाइप-2 और टाइप-3 की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।सैन्य क्षेत्र में यह स्वदेशी निर्माताओं को मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर

दोहरी सामरिक चुनौती के मद्देनजर रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। यह अब तक स्वदेशी निर्माताओं को मिलने वाला सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। परिषद ने नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए लड़ाकू पोत के हल्के प्लेटफॉर्म से सतह पर मार करने वाली मध्यम रेंज की एंटी शिप मिसाइल (एमआरएएसएचएम) की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

एमआरएएसएचएम नौसेना के जहाजों पर प्राथमिक आक्रामक हथियार होगा। परिषद में मिली रक्षा उत्पादों की एओएन के बाद अब निर्माताओं के साथ कीमत निर्धारण के लिए नेगोशिएशन किया जाएगा। अंतिम कीमत निर्धारित हो जाने के बाद प्रस्ताव अंतिम निर्णय के लिए रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के समक्ष रखें जाएंगे। वहां से मंजूरी के बाद खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

मोदी सरकार ने चीन से लगी 4000 किमी लंबी सीमा पर इंफ्रास्ट्रकचर पर दिया जोर

इससे पहले पीएम मोदी के दिशा निर्देशन में भारत में निर्मित जंगी जहाजों और पनडुब्बियों ने नेवी की मारक क्षमता को और बढाया। सेना के पास अब भारत में बने टैंक, मिसाइल और हैंड ग्रेनेड हैं जो आत्मनिर्भर भारत के नारे को चार चांद लगा रहे हैं। सुरक्षा के लिए साजो-सामान का इंतजाम करने के साथ साथ मोदी सरकार ने चीन से लगी रास्ते जल्दी से जल्दी पहुंचने का रास्ता भी बनाने पर जोर दिया। इसके शानदार नतीजे देश के सामने हैं। अब अगर चीन आंखें तेरेरता है तो भारत की सेना उनकी आंखों में आंखे डाल कर बात करती है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की बोलती बंद है। आलम ये है कि पहले जहां सीमा पार से हुई गोलीबारी का जवाब देने के लिए दिल्ली से पूछना पड़ता था, अब सीमा पर मौजूद कमांडर को खुद ही निर्णय लेने का अधिकार मिल गया है। इससे आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी के साथ ही सरहदें और सुरक्षित हुई हैं।

दुनिया को भरोसा दिलाने के लिए पीएम मोदी ने भरी थी स्वदेशी तेजस में उड़ान!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमटेड (HAL) की फैसिलिटी के दौरे पर गए थे। यहां उन्होंने तेजस के मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान पीएम मोदी ने एक को-पायलट की भूमिका निभाते हुए मेड-इन-इंडिया फाइटर जेट तेजस में उड़ान भरी। तेजस भारत की आत्मनिर्भरता की झलक है। तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। यह HAL द्वारा विकसित एक सीट और एक जेट इंजन वाला, अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का युद्धक विमान है। इस विमान ने दुनिया को भारतीय टेक्नोलॉजी की खूबियों से परिचित कराया है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े-बड़े देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने तेजस में उड़ान इसलिए भरी जिससे कि दुनिया के देशों में तेजस प्रति विश्वास बहाल हो सके और दुनिया के देश इसे खरीदने के लिए आगे आएं।

पीएम मोदी के उड़ान भरने से यह साबित हो गया कि तेजस सुरक्षित फाइटर जेट है। लेकिन नकारात्मकता में जीने वाली कांग्रेस को पीएम मोदी की फोटो देखकर मिर्ची लग गई और उसने इस पर भी तंज कसते हुए इसे चुनावी फोटो सेशन करार दिया। पीएम मोदी रक्षा में आत्मनिर्भरता को महत्व दे रहे हैं और फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाले भारत के पहले पीएम बन गए हैं लेकिन कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही है।

आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर, 2023 को तेजस में उड़ान भरने के बाद कहा कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी।

पूर्वोत्तर में शांति के नए युग की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मणिपुर सरकार के लगातार प्रयास से पूर्वोत्तर में शांति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के अथक कोशिशों से मणिपुर में 60 साल पुराना विषय खत्म हो चुका है। मणिपुर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना उग्रवादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) ने हथियार डाल दिया है। यूएनएलएफ ने केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हिंसा छोड़ने और मुख्यधारा में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की। इससे मणिपुर के साथ ही पूरे देश के लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताया है।

प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के अथक प्रयास से हुआ शांति समझौता- एन बीरेन सिंह - शुक्रवार बीरेन सिंह ने कहा कि मैं मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर में शांति बहाल करने की पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही बीरेन सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह के "अथक प्रयासों" के लिए आभार व्यक्त किया और बताया कि उनकी पहल से शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मणिपुर के सीएम ने कहा कि शांति वार्ता के प्रयास कई सालों से किए जा रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। शांति समझौते पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ। यह बीजेपी द्वारा पूर्वोत्तर में बनाए गए विश्वास का नतीजा है।

पूर्वोत्तर में शांति के अथक प्रयासों में एक नया अध्याय जुड़ गया है- अमित शाह

केंद्र सरकार और यूएनएलएफ के बीच बुधवार को दिल्ली में समझौता हुआ। इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के मोदी सरकार के अथक प्रयासों में एक नया अध्याय जुड़ गया है क्योंकि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) ने आज नई दिल्ली में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। मणिपुर का सबसे पुराना घाटी स्थित सशस्त्र समूह यूएनएलएफ हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने पर सहमत हो गया है। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका स्वागत करता हूं और शांति और प्रगति के पथ पर उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार मीटिंग के बाद बनाई थी रणनीति

राज्य में तीन मई 2023 को जातीय हिंसा भड़कने के बाद यह पहली बार है कि किसी बड़े उग्रवादी समूह ने शांति के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने समझौते से दो दिन पहले ही मणिपुर में शांति स्थापित करने के संकेत दे दिए थे। समझौते के लिए उन इलाकों की पहचान की गई थी जहां यह संगठन सक्रिय था। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों और पूर्वोत्तर के राज्यों से आने वाले मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार मीटिंग की। पिछले कुछ सालों में एक खास रणनीति के तहत गृहमंत्रालय ने इस ग्रुप के साथ समझौते की योजना बनाई। इस ग्रुप के गठन और इसको बढ़ावा देने में चीन परोक्ष रूप से मदद देता रहा है। यह संगठन मणिपुर में पुलिस और नागरिकों पर हमलों के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल था। वर्ष 1990 में इस संगठन ने भारत से मणिपुर की 'मुक्ति' के लिए एक सशस्त्र संघर्ष शुरू किया था।

J&k : मोदी सरकार के फैसले पर 'सुप्रीम' मुहर, 2024 में विधानसभा चुनाव कराने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 अस्थायी प्रावधान था। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच जजों की खंडपीठ ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को सही करार दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि भारत में विलय के साथ ही जम्मू-कश्मीर ने अपनी संप्रभुता खो दी थी। लिहाजा भारत के राष्ट्रपति का आदेश अंतिम और सर्वमान्य होगा। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए 2019 में जब संसद में बिल लाया गया था तब कांग्रेस पार्टी ने ही इसका जोरदार विरोध किया था। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और तुष्टिकरण में जुटी रहने वाली कुछ अन्य पार्टियों ने तो यहां तक कहा था कि 370 को हटाया ही नहीं जा सकता। आज का फैसला उन सभी के मुंह पर तमाचा है जो देश की एकता को मजबूत करने की जगह विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते रहे थे। कोर्ट की सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने तो राज्य में जनमत संग्रह की मांग कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखने पर इसे ऐतिहासिक करार दिया है।

कांग्रेस व लेफ्ट लिबरल को अनुच्छेद 370 सहित दर्जनों मामलों में मिली हार

कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल और लेफ्ट लिबरल अब तक मोदी सरकार के खिलाफ दर्जनों में मामलों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और अनुच्छेद 370 की ही तरह हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। ये लोग अब तक जीएसटी, सी.ए.ए, सीबीआई, ईवीएम, पीएमएलए, यूएपीए, आधार, पेगासस, राम मंदिर, राफेल डील, तीन तलाक, गुजरात दंगे, सेंट्रल विस्टा, पीएम केयर्स फंड, नोटबंदी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ अदालत जा चुके हैं और हर बार हार का सामना करना पड़ा है।

यह एक कानूनी फैसला नहीं, आशा की किरण है: पीएम मोदी

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है। जिसमें भारतीय संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले की संवैधानिकता बरकरार रखी गई है। यह उम्मीदों, विकास और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के हमारे भाई-बहनों की एकता की गूंज है। अदालत ने हमारी एकता के मूल के सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय सबसे ऊपर रखते हैं। आज का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है बल्कि यह आशा की

किरण है। यह उज्जवल भविष्य का वादा है और हमारे उन एकजुट प्रयासों का सबूत है, जिनसे हम एक मजबूत और एकजुट भारत बनाएंगे।'

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सही माना

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही माना। इस मामले में 5 सितंबर 2023 को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। राज्य के बारे में केंद्र सरकार और राष्ट्रपति फैसला ले सकते हैं। अदालत ने माना कि विधानसभा निरस्त होने के बाद संसद को जम्मू-कश्मीर के मामले में कानून बनाने का अधिकार था।

370 को स्थायी व्यवस्था कहने वाली याचिका खारिज

फैसला सुनाने की शुरुआत करते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया कि अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने अपना-अपना फैसला सुनाया है। 5 जजों की बेंच में तीन अलग-अलग फैसले थे मगर निष्कर्ष एक ही था। अनुच्छेद 370 को स्थायी व्यवस्था कहने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुनाते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र, राष्ट्रपति की भूमिका के तहत सरकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद या राष्ट्रपति उद्घोषणा के तहत किसी राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 खत्म करने की शक्ति थी

अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में शामिल होते ही जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। CJI ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता भी नहीं थी। इसका संविधान भारत के संविधान के अधीन था। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 खत्म करने की शक्ति थी।

अस्थायी प्रावधान था संविधान का अनुच्छेद 370

CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारा मानना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। हस्तांतरण के उद्देश्य से इसे लागू किया गया था। राज्य विधानसभा के गठन के लिए इसे अंतरिम तौर पर लागू किया गया था। सीजेआई ने कहा कि राज्य में युद्ध के हालात के चलते विशेष परिस्थितियों में इसे लागू किया गया था। इसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति के आदेश की संवैधानिकता पर सीजेआई ने कहा कि फैसले के वक्त राज्य की विधानसभा भंग थी, ऐसे में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का नोटिफिकेश जारी करना राष्ट्रपति की शक्तियों के तहत आता है।

जम्मू-कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं

CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि जम्मू कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता है। युवराज कर्ण सिंह की साल 1949 में की गई उद्घोषणा और संविधान से इसकी पुष्टि होती है। संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत ही जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था। भारत में विलय के बाद जम्मू-कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं बची थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रपति की रोजमर्रा के कामकाज संबंधी शक्तियों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। संविधान के अनुच्छेद 357 के तहत राज्य की विधानसभा की कानून निरस्त करने या संशोधित करने की शक्ति को संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई

CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं था कि वह जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही 370 पर कोई आदेश जारी करें। अनुच्छेद 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई।

न्यायमूर्ति कौल और न्यायमूर्ति खन्ना ने अपने फैसले अलग-अलग दिए वहीं, न्यायमूर्ति खन्ना ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को धीरे-धीरे अन्य भारतीय राज्यों के बराबर लाना था। उन्होंने राज्य और राज्येतर तत्वों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए एक सत्य-और-सुलह आयोग के गठन का निर्देश दिया।

उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

देहरादून के एफआईआर में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश-दुनिया के इन्वेस्टर और डेलीगेट्स शामिल हुए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहले दिन क्षेत्र में अपने निवेश और इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दी। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन और एमडी सज्जन जिंदल ने भी कार्यक्रम में अपने संबोधन से अपने प्लान की जानकारी दी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहले दिन 44 हजार करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए।

अमित शाह ने कहा कि भारत 2025 के अंत तक 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने यहां उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन (उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट) के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण भारत पिछले एक दशक में हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ा है। शाह ने कहा कि दुनिया आज भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। 2014 से 2023 के बीच भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था से उठकर पांचवीं (सबसे बड़ी) अर्थव्यवस्था बन गया है।

देश ने पहले कभी इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई

उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल के दौरान देश ने पहले कभी इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई। उन्होंने इसका श्रेय मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने की उनकी क्षमता को दिया।

शाह ने कहा कि मोदी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वह आतंकवाद मुक्त दुनिया के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान की अगुवाई करने के अलावा अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिये दुनिया की धीमी होती जीडीपी को गति देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी-20 दिल्ली घोषणापत्र कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बड़ी उपलब्धि है, जिसे दुनिया आने वाले दशकों तक याद रखेगी।

डबल इंजन सरकार की प्राथमिकताओं का उत्तराखंड को कैसे डबल फायदा मिल रहा है, इसका एक उदाहरण टूरिज्म सेक्टर भी है। आज भारत को देखने के लिए भारतीयों और विदेशियों, दोनों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। हम पूरे देश में थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट तैयार कर रहे हैं। कोशिश ये है कि भारत के नेचर और हैरिटेज, दोनों से ही दुनिया को परिचित कराया जाए। इस अभियान में उत्तराखंड, टूरिज्म का एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरने वाला है। यहां नेचर, कल्चर, हैरिटेज सब कुछ है। यहां योग, आयुर्वेद, तीर्थ, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हर प्रकार की संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को एक्सप्लोर करना और उन्हें अवसरों में बदलना, ये आप जैसे साथियों की प्राथमिकता ज़रूर होनी चाहिए। और मैं तो एक और बात कहूंगा शायद यहां जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे, बुरा लगे लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहां नहीं हैं। खासकर के देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं। मिलेनियर्स-बिलेनियर्स से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना वो जोड़े ईश्वर बनाता है। ईश्वर तय करता है ये जोड़ा। मैं समझ नही पा रहा हूं जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने की बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसा है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेडिंग इन इंडिया। शादी हिन्दुस्तान में करो।

जनता को जोड़ने के मामले में यूपी नंबर वन

नरेन्द्र मोदी के विजन को मिशन के रूप में धरातल पर उतार रही योगी सरकार देश में चल रही तमाम योजनाओं में शीर्ष स्थान पर है। इस कड़ी में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा का नाम भी जुड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देश में प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि बीते 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। अबतक देशभर में एक करोड़ से अधिक नागरिक इस अभियान से जुड़ चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 37 लाख से अधिक लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। ये सिलसिला हर नये दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार और जनता के बीच संबंधों को मजबूत आधार देने का सशक्त और परिवर्तनकारी अभियान बन चुका है। इसके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए ऑन दि स्पॉट रजिस्ट्रेशन, ड्रोन दीदी अभियान के तहत ड्रोन वितरण, शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार खासकर महिला केंद्रित योजनाओं के लिए जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि वे अपने लाभ के लिए सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें। इस अभियान में उत्तर प्रदेश के 57709 ग्राम पंचायतों और 777 नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को प्रदेश के 10 जिलों के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया है। इनमें चंदौली, अमेठी, खीरी, गाजियाबाद, फतेहपुर, लखनऊ, आगरा, जालौन, मीरजापुर और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। इन सभी दस जिलों में केंद्रीय और प्रदेश सरकार के मंत्रीगण भी उपस्थित रहे।

जनता के साथ संवाद कायम कर रहे जनप्रतिनिधि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी निर्देश हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करायी जाये। इसके अलावा मंत्रीगण एवं राज्यपाल को भी किसी जनपद में आगमन पर कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाये। साथ ही साथ सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख को विकसित भारत संकल्प यात्रा की कार्य योजना की प्रति उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा युवक मंगल दल, युवती मंगल दल, पीआरडी, होम गार्ड आदि युवा संगठनों के माध्यम से अधिक से अधिक 15-29 वर्ष के युवाओं को "माई युवा भारत" में पंजीकृत कराया जाये। साथ ही नागरिकों को नमो मोबाइल ऐप के सम्बन्ध में जागरूक कर इस ऐप से जोड़ा जाये। इस अभियान के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जनपदों में आवंटन के अतिरिक्त मोबाइल वैन की आपूर्ति भी कराई जा रही है, जिन्हें ग्राम पंचायतों में लगाया जा रहा है। अभियान में लगभग पांच सौ वाहनों को लगाया गया है, जो शहरी और ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर जनता से संवाद, विभिन्न योजनाओं के लिए ऑन दि स्पॉट रजिस्ट्रेशन और जागरूकता बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

सीएम का निर्देश, लेखपाल से लेकर सीएससी प्रतिनिधि तक ही हो दैनिक उपस्थिति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस बात के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में स्थानीय लेखपाल, कृषि विभाग के कर्मचारी, प्राथमिक विद्यालयों के हेड मास्टर, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा बहुएं, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, समूह सखी, पोस्ट मास्टर और कॉमन सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि की दैनिक उपस्थिति को सत्यापित किया जाए।

लाउडस्पीकर और खुले में मांस बिक्री पर लगाई रोक

शपथ ग्रहण के बाद डॉ. मोहन यादव ने सबसे पहले खुले में मांस विक्रय पर रोक लगाई और उसके बाद लाउडस्पीकर की आवाज कम कराने का फैसला लिया था। इन दो फैसलों के बाद वे लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी भी उत्तर प्रदेश में ऐसा कर चुके हैं। ऐसी किंवदंती है कि महाकाल की नगरी उज्जैन के राजा स्वयं महाकाल ही हैं। यदि कोई राजा (राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री) यहां रुकता है तो इसके बाद उसके सामने ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो सत्ता से बाहर हो जाता है। यह मान्यता दो बार सच भी साबित हुई है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक बार रात्रि में महाकाल की नगरी में रुके थे। दूसरे ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। इसी प्रकार कर्नाटक के सीएम येदुरप्पा भी एक बार महाकाल की नगरी में रात्रि विश्राम कर चुके हैं। उज्जैन में रहने के 20 दिन बाद ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

एमपी में मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहला एक्शन लिया है. जिसमें राजधानी भोपाल में भाजपा नेता की हथेली काटने वाले पांच आरोपियों के तीन घरों को बुल्डोजर चलाकर ढहा दिया गया है. आरोपियों ने पांच दिसम्बर को झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ अरेरा मंडल के महामंत्री देवेंद्र सिंह ठाकुर की हथेली काट दी थी. हमले के 9वें दिन आरोपियों पर कार्रवाई हुई. डॉण् मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला एक्शन है.

मध्यप्रदेश में 16वीं विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरु हो गया. चार दिन तक चलने वाले इस नव-निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई है. वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया. नरेन्द्र सिंह तोमन निर्विरोध चुने जाएगें क्योकि उन्हे विपक्ष का भी साथ मिला है. विधानसभा अध्यक्ष का चयन 20 दिसंबर को होगा. प्रोटेम स्पीकर उन्हें शपथ दिलाएंगे.

इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष के साथ मिलकर सकारात्मक प्रदेश के लिए बेहतर काम करेगें. महाकाल लोक, ओरछा सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर अनुष्ठान करेंगे. विधायक-मंत्रियों के लिए प्रशासनिक दक्षता की ट्रेनिंग कराई जाएगी. उन्होने आगे कहा कि आज 16वीं विधानसभा के सत्र का पहला दिन है. मुझे इस बात की खुशी है कि आज सत्ता पक्ष-विपक्ष ने मिलकर नए विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन दाखिल किया है. मैं विधायक दल के नेता के नाते विपक्ष की सकारात्मक सोच का स्वागत करता हूं. विपक्ष इसी तरह अपना रचनात्मक सहयोग दे. हम प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे. सीएम श्री यादव ने कहा कि महाकाल लोक, ओरछा सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर अनुष्ठान शुरू होंगे. विधायक और मंत्रियों की प्रशासनिक दक्षता की ट्रेनिंग कराई जाएगी. मंत्रिमंडल गठन पर उन्होंने कहाए श्कल दिल्ली में बैठक हुई है. जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा.

ध्यप्रदेश में 16वीं विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरु हो गया. चार दिन तक चलने वाले इस नव-निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई है. वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया. नरेन्द्र सिंह तोमन निर्विरोध चुने जाएगें क्योकि उन्हे विपक्ष का भी साथ मिला है.

मुख्यमंत्री के फैसले से जन-जन में जागा विश्वास

पूरे होंगे छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया है कि राज्य के 18 लाख से अधिक हितग्राहियों का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का आवास बनवाया जाएगा। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी साथ ही मनरेगा के अंतर्गत 90 दिनों का रोजगार भी मिलेगा।

- खुशहाली के आशियाने से बदलेगी जिन्दगी, टपकते छत की सालाना मरम्मत से मिली राहत
- बंदरों की उछलकूद से खपरैल टूट जाती थी, अब मिलेगा पक्का मकान
- टेकारी में गांव वालों पीएम आवास मिलने के निर्णय से काफी खुशी

अब पक्का मकान बन जाने से घर में पानी भर जाने और सिलन की समस्या नहीं होगी और मेहमान भी उनके घर आराम से रुक सकेंगे। इसी तरह गांव के अन्य हितग्राही बताते है कि छत कमजोर हो जाने के कारण उन्होंने खपरे की जगह टीने का शीट लगावाया है। पर बंदरों के उछलकूद के कारण इस शीट से बहुत आवाज आती है जिससे उनको परेशानी होती है। पक्का मकान बन जाने से अब उन्हें इस समस्या से राहत मिलेंगी और इसके लिए वह मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते है। - ओमकुमारी वर्मा

रायपुर जिले के पास स्थित टेकारी गांव के निवासी प्राकृतिक आपदा और बंदरो द्वारा पैदा की गई आपदाओं से परेशान रहते हैं। बारिश के मौसम में उनके जीर्ण-शीर्ण घरों में छत से पानी टपकाने लगता है और रही सही कसर बंदरों की उछल कूद से पूरी हो जाती है। मकान के मेंटेनेंस का खर्चा इन ग्रामीणों पर बहुत भारी पड़ता है प्रधानमंत्री श्री मोदी के गारंटी के पश्चात मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा 18 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जाने के निर्णय से टेकारी के ग्रामीणों में भी काफी खुशी की लहर है ,अब उन्हें हर साल होने वाली समस्या से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। रायपुर जिले के आरंग विकासखण्ड के ग्राम टेकारी के हितग्राहियों में मुख्यमंत्री के पक्का आवास देने के फैसले के बाद भारी उत्साह है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि अब हमारा भी पक्का मकान होगा। गांव के हितग्राही मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि उन्होंने पूर्व में प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था, पर उनका आवास स्वीकृत नहीं बन पाया था। वह कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद अब मेरा भी पक्का आवास होगा इस बात कि अब मुझे बहुत खुशी है। इसी तरह गांव के ही अन्य हितग्राही टेकारी ग्राम के बस्ती पारा निवासी मुकेश धीवर बताते हैं कि उनके घर में दस लोग रहते हैं। कच्चा मकान होने के कारण बारिश के दिनों में उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। वर्षा के कारण छत से पानी टपकने लगता था और हमें सोने में समस्या होती थी। हम किसी तरह पॉलिथीन का उपयोग करके छत की मरम्मत करते थे, पर वह भी कारगर साबित नहीं होता था पर पक्का आवास बनने से हमें इस समस्या से राहत मिलेगी। इनकी माता श्रीमती सोनी धीवर कहती है कि अब मुझे लग रहा है कि हमें पक्का मकान में रहने मिल जाएगा, जिससे बंदरों के उछल-कूद से घर के छत में होने वाले नुकसान से निजात मिलेगी। गांव की अन्य हितग्राही श्रीमती लक्ष्मी वर्मा कहती है कि उनके मकान की रसोईघर की छत कमजोर हो जाने के कारण गिर गई थी, परन्तु उस समय रसोईघर में किसी के न होने के कारण बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उनके पति लाल जी वर्मा बताते है कि गाय के कोठे की छत भी कमजोर होने के कारण एक बार गिर गई थी। साथ ही गांव में बन्दरों की उछल-कूद से खपरैल भी टूट जाते है। जिसकी मरम्मत के लिए उन्हें हर वर्ष 20 हजार रूपये खर्च करने पड़ते थे साथ ही कच्चे मकान की वजह से सांप-बिच्छू का खतरा भी बना रहता था। गांव के खाल्हेपारा में रहने वाले अशोक वर्मा बताते है कि बंदरो के उत्पाद के कारण उनके मकान की छत कमजोर हो गई है। छत को गिरने से बचाने के लिए उन्होंने लकड़ी की बल्लियों का सहारा लिया है। उनकी बेटी ओमकुमारी वर्मा बताती है कि पानी गिरने पर घर की छत टपकने लगती है और घर में पानी भरने लगता है। जिससे उनकी पढ़ाई में भी दिक्कतें आती थी। साथ ही मेहमानों के आने पर उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ता था जिसके कारण वह नहीं रुक पाते थे।

कॉन्ग्रेस सांसद के ठिकानों पर IT छापे में मिला नोटों का पहाड़, ₹300 करोड़ से ज्यादा बरामद

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद साल 2024 लोकसभा चुनावों से पहले कॉन्ग्रेस पार्टी को उनके ही सांसद धीरज प्रसाद साहू ने और मुसीबत में डाल दिया है। आयकर विभाग ने 9 दिसंबर 2023 को झारखंड कॉन्ग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर छापेमारी के बाद सैकड़ों करोड़ रुपए कैश और अन्य बेहिसाब सम्पत्तियाँ बरामद की हैं। कॉन्ग्रेस सांसद की संपत्ति की जाँच अभी भी जारी है जिस से बरामदगी की राशि और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए से अधिक बेनामी सम्पत्ति बरामद होने का मामला चर्चा में आते ही कॉन्ग्रेस ने खुद को इस विवाद से अलग करने का प्रयास किया।

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की छापेमारी से बरामद हुआ पैसा ओडिशा स्थित बुद्धा डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उसके जुड़े संगठनों से संबंधित है। कॉन्ग्रेस सांसद धीरज साहू का कोई बंटी नाम का सहयोगी भी प्रकाश में आया है जो ओडिशा के कई हिस्सों में शराब कारोबार को संभालता है। बंटी के घर से कैश भरे उन्नीस बैग मिले हैं। इस कैश को गिनने के लिए तीन दर्जन मशीनें लगाई गई हैं जिसमें से कुछ गिनती के तौर खराब भी हो गई थीं। इसी खराबी के चलते बरामदगी गिनने में अतिरिक्त समय लगा।बोलांगीर में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक भगत बेहेरिया ने कथित तौर पर बताया है कि बैंक को नोटों से भरे कुल 176 बैग मिले हैं। इन नोटों को गिनने के लिए 25 काउंटिंग मशीनों के साथ 50 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

कौन हैं धीरज प्रसाद साहू

धीरज प्रसाद साहू का परिवार पुराना कॉन्ग्रेसी है। राज्यसभा की वेबसाइट के मुताबिक धीरज साहू अपने परिवार को आजादी के समय से ही कॉन्ग्रेस से जुड़ा बताते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि वो साल 1978 में जेल भरो आंदोलन का हिस्सा भी थे। वो बुद्धा डिसिलरिज ग्रुप की कंपनी की बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनर हैं। धीरज प्रसाद ने अपने राजनैतिक कैरियर की शुरुआत साल 1977 में नेशनल लीडर यूनियन ऑफ इंडिया (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी) के एक मेंबर के तौर पर शुरू किया था। धीरे-धीरे वो इस क्षेत्र में मंझते चले गए बाद में कॉन्ग्रेस ज्वाइन कर लिया। धीरज ने झारखंड कॉन्ग्रेस के बड़ी बड़े दायित्व भी संभाले हैं। साल 2009 में धीरज साहू पहली बार उपचुनाव में राज्यसभा सदस्य चुने गए। इसी पद पर साल 2010 में फिर उनका चयन हुआ। मई 2018 में वह तीसरी बार झारखंड से कॉन्ग्रेस पार्टी से राज्यसभा गए। साल 2010 से अब तक सांसद साहू ने राज्यसभा में कुल 630 सवाल किए हैं। ये प्रश्न नवीनतम कवच सुरक्षा प्रणाली, धान की खरीद, राष्ट्रीय राजमार्ग, कोयला खनन, हवाई अड्डों के निजीकरण आदि मामलों से जुड़े हैं। धीरज प्रसाद साहू ने नवंबर 2022 में राहुल गाँधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिया था।

पूर्वी क्षेत्र ने समग्र देश के औद्योगिक विकास की नींव रखी

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज बिहार की राजधानी पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमारऔरझारखंड, ओड़ीशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। बैठक में अंतर राज्य परिषद सचिवालय की सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

अपने सम्बोधन में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र देश की सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ ही प्राचीन काल से आज तक अनेक प्रमुख शिक्षण संस्थानों का केन्द्र रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे प्रयोग हुए और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूर्वी क्षेत्र के बच्चे ही सबसे ज्यादा सफल होते हैं।गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्वी क्षेत्र ने समग्र देश के औद्योगिक विकास की नींव रखी हैऔरआज़ादी से पहले और बाद इस क्षेत्र के अनेक राष्ट्र भक्तों ने देश के पुनर्विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।यह क्षेत्र खनिज संपदा और पानी से संपन्न है और बिहार, उड़ीसा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों ने पूरे देश की जरूरतों के लिए लगभग सभी खनिज संसाधन उपलब्ध कराए हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने का जो विजन दिया है पिछले 9 साल में उसे चरितार्थ भी किया है। श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की संख्या में हुई बढोत्तरी के आंकडे देते हुए गृह मंत्री ने बताया कि 2004 से मई 2014 तक क्षेत्रीय परिषदों और इनकी स्थायी समितियों की बैठकों की कुल संख्या मात्र 25 थी और इस दौरान हर वर्ष औसतन 2.7 बैठकें आयोजित हुई। लेकिन वर्ष जून 2014 से अब तक पिछले 9 वर्षों में, कोविड-19 महामारी के बावजूद, क्षेत्रीय परिषदों और इनकी स्थायी समितियों की कुल 56 बैठकें हुई और हर साल औसतन 6.2 बैठकें आयोजित हुई।इस वर्ष अभी तक कुल 9 बैठकें हुई हैं जिसमें क्षेत्रीय परिषदों की चार और स्थायी समितियों की पाँच बैठकें शामिल है। उन्होंने कहा कि बैठकों की संख्या में दोगुनी से अधिक बढोत्तरी प्रधानमंत्री मोदी जी के टीम इंडिया कॉन्सेप्ट को उद्घोषित करती हैं।

लगभग तीन घंटे चली बैठक को संबोधित करते हुएगृह मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में 1157मुद्दों को सुलझाया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में राजनीतिक मामलों पर मतभेद भुलाकर उदारवादी तरीके से मामलों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।श्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के अनके मुद्दों को भी क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के एजेंडे में शामिल किया गया है। इनमें पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों में कुपोषण को दूर करना, स्कूली बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर कम करना, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सरकारी अस्पतालों की भागीदारी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इसके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSC) का कार्यान्वयन, प्रत्येक गांव के 5 किमी के भीतर बैंकों/इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखाओं की सुविधा, देश में दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACSs) की स्थापना और देश के सभी मौजूदा पैक्सों को मजबूत करना शामिल है।उन्होंने कहा कि इन विषयों पर मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर हर तीन महीने पर समीक्षा किए जाने की जरूरत है। बैठक में खनन, कुछ मदों में केन्द्रीय आर्थिक सहायता, बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, भूमि अधिग्रहण एवं भूमि स्थानांतरण, जल बँटवारा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम का कार्यान्वयन, राज्य पुनर्गठन से सम्बंधित मुद्दे तथा क्षेत्रीय स्तर के सामान्य हित के विषयों पर भी चर्चा हुई।

108 गांवों को किया गया अधिसूचित - यूपीडा की ओर से चिह्नित सभी 30 स्थलों से जुड़े 108 गांवों को प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचित किया जा चुका है। वहीं, भूमि क्रय के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को 200 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। साथ ही भूमि क्रय के लिए बुंदेलखंड औद्योगिक प्राधिकरण की तर्ज पर 1500 करोड़ रुपये अवमुक्त किए जाने का आदेश भी निर्गत किया जा चुका है। जिला स्तर पर भूमि क्रय के लिए दरों का निर्धारण फिलहाल प्रक्रिया में है।

लगभग तीन घंटे चली बैठक को संबोधित करते हुएगृह मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में 1157मुद्दों को सुलझाया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में राजनीतिक मामलों पर मतभेद भुलाकर उदारवादी तरीके से मामलों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।श्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के अनके मुद्दों को भी क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के एजेंडे में शामिल किया गया है। इनमें पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों में कुपोषण को दूर करना, स्कूली बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर कम करना, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सरकारी अस्पतालों की भागीदारी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इसके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSC) का कार्यान्वयन, प्रत्येक गांव के 5 किमी के भीतर बैंकों/इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखाओं की सुविधा, देश में दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACSs) की स्थापना और देश के सभी मौजूदा पैक्सों को मजबूत करना शामिल है।

एआई का जब सही ढंग से उपयोग किया जाता है, तो यह स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शासन और भाषा अनुवाद को बदल सकता है

- "आज, भारत के युवा स्टार्टअप भारतीय बाजार और दुनिया के लिए डिवाइस, आईपी उत्पाद, समाधान और प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहे हैं": राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
- "आज हम जिन फ्यूचर डिजाइन डीएलआई स्टार्टअप्स का समर्थन कर रहे हैं, उनमें भविष्य की यूनिकॉर्न बनने की क्षमता है": राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर
- "हमारा मानना है कि एआई का जब सही ढंग से उपयोग किया जाता है, तो यह स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शासन और भाषा अनुवाद को बदल सकता है": राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर
- "दुनिया अब भारत के विजन के साथ जुड़ रही है कि हमें इंटरनेट के लिए सुरक्षा और विश्वास की रेलिंग की आवश्यकता है": राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर
-

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर 26वें बेंगलुरु टेक में सिलिकॉन डिजाइन इंजीनियरिंग, एएमडी इंडिया की कंट्री हेड, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती जया जगदीश के साथ गुरुवार को शिखर सम्मेलन के दौरान गहन बातचीत में शामिल हुए। राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के बढ़ते सेमीकंडक्टर उद्योग, एआई और देश के समग्र आर्थिक विकास में स्टार्टअप द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। सेमीकॉन इंडिया 2023 शिखर सम्मेलन को याद करते हुए, श्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के आख्यान के सशक्त परिवर्तन पर प्रकाश डाला, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने परिकल्पना की थी।

श्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा, "हमने गांधीनगर में 2023 सेमीकॉन इंडिया शिखर सम्मेलन में पूरी कहानी में बदलाव देखा, जहां लोग अब "भारत क्यों" पूछने से हटकर "हम भारत में ऐसा कब करने जा रहे हैं, और हम भारत में ऐसा क्यों नहीं?" करने लगे हैं।" इस बदलाव के कई अंतर्निहित कारण हैं, हालांकि, भू-राजनीति के अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारक, पिछले कुछ वर्षों में विकसित इको-सिस्टम का बढ़ता आत्मविश्वास और क्षमताएं हैं। पिछले पांच से सात वर्षों में, हमारी तकनीकी अर्थव्यवस्था दुनिया भर में जो कुछ भी चल रहा है उसके लगभग हर पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। चाहे वह एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेब 3, सुपरकंप्यूटिंग, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग ही क्यों न हो।

डिजाइन में विरासत की कमी के बावजूद सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की तीव्र प्रगति पर जोर देते हुए, श्री चंद्रशेखर ने कहा, "मेरा मानना है कि दशकों तक अवसर चूकने के बाद अब हम कैच-अप खेल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई मायनों में, हम लगभग एक पीढ़ी को छोड़ रहे हैं और अगले दशक के लिए उन अवसरों की तलाश कर रहे हैं जो पूरी तरह से नए हैं और अद्वितीय अवसर पेश करते हैं। आज दुनिया के लिए उपकरण डिजाइन करना एक ऐसी चीज है जिसकी भारत में कोई विरासत नहीं है। इसलिए, मेरा मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में, हमने प्रतिभा, डिजाइन, पैकेजिंग और अनुसंधान में जबरदस्त प्रगति की है।

एक सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा और बदले में, वैश्विक सेमीकंडक्टर इको-सिस्टम में एक विश्वसनीय हस्ती बनने की ओर अग्रसर है। यह इस बात पर निर्भर है कि हम इसे कितनी जल्दी कार्यान्वित कर सकते हैं।"

श्री राजीव चन्द्रशेखर ने स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और शासन में एआई के इस्तेमाल पर जोर देते हुए इसका लाभ उठाने के लिए सरकार के विजन पर जोर दिया। एआई द्वारा प्रस्तुत विशाल अवसरों को स्वीकार करते हुए, उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले संभावित खलनायकों की उपस्थिति के बारे में भी बात की। उन्होंने सुरक्षा और विश्वास के लिए विधायी रेलिंग की आवश्यकता पर बल दिया।

एआई के बारे में श्री चंद्रशेखर ने कहा, "हमारा मानना है कि एआई, जब सही ढंग से उपयोग किया जाता है, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शासन और भाषा अनुवाद को बदल सकता है। हमारा ध्यान एआई पर कब्जा करने, क्षमताओं और डेटासेट का निर्माण करने और मॉडल बनाने के लिए एआई गणना और प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाने पर है जो भारत के जीवन को बेहतर बनाने के लक्ष्यों में योगदान देगा। एआई 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए एक गतिशील प्रवर्तक है जिसे हमने एक राष्ट्र के रूप में अपने लिए निर्धारित किया है। हालांकि, जैसा कि हाल की बातचीत से पता चला है, दुनिया अब भारत के इस विजन के साथ जुड़ रही है कि हमें सुरक्षा और विश्वास की रेलिंग की आवश्यकता है। इसलिए, भले ही एआई महान है, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और विश्वास की विधायी रेलिंग की आवश्यकता है कि एआई का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है या खलनायकों द्वारा नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।"

उड़ान योजना से 130 लाख से अधिक लाभान्वित

जनता के लिए किफायती दरों पर हवाई सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना को प्रोत्साहन देने के लिए मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के अपर्युक्त और कम उपयोग वाले हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

LOK SHAKTI 25

उड़ान योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

I) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना - उड़ान को क्षेत्रीय मार्गों को जोड़ने वाले कम सेवा वाले/अपर्युक्त मार्गों पर हवाई परिचालन को बढ़ावा देने और जनता के लिए उड़ान को किफायती बनाने के लिए बनाया गया है। ii) केंद्र, राज्य सरकारों और हवाईअड्डा संचालकों की ओर से रियायतों के संदर्भ में वित्तीय प्रोत्साहन चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों को दिया जाता है ताकि कम सेवा वाले/अपर्युक्त हवाई अड्डों/हेलीपोर्ट/जल हवाई अड्डों से परिचालन को प्रोत्साहित किया जा सके और हवाई किराया वहनीय रखा जा सके। iii) चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों को वित्तीय सहायता व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के रूप में है। राज्य सरकारें अपने राज्यों से संबंधित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ानों के लिए वीजीएफ के लिए 20 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करती हैं। पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वीजीएफ की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है। iv) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ानों के लिए आरसीएस हवाई अड्डों पर चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों द्वारा शुरू की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निकाले गए एविएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर एक प्रतिशत/दो प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। v) एयरलाइंस को आरसीएस उड़ानों में विमान के प्रकार और आकार के आधार पर सीटों की एक निश्चित संख्या को आरसीएस सीटों के रूप में प्रतिबद्ध करना आवश्यक है। vi) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी फंड (आरसीएफ) पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह के मार्गों पर उड़ानों के प्रस्थान को छोड़कर 40 टन से अधिक एमटीओडब्ल्यू (अधिकतम टेक-ऑफ वजन) वाले विमानों पर उड़ानों के प्रत्येक प्रस्थान पर लेवी द्वारा बनाया गया है।vii) संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए, मार्ग आवंटन देश के पांच क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर पूर्व (किसी दिए गए क्षेत्र में 30 प्रतिशत की सीमा के साथ) में समान रूप से फैला हुआ है।।

देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले वीर जवान, देश के विकास की नींव हैं

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज झारखंड के हज़ारीबाग में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 59वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। श्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल की वार्षिक पत्रिका 'बॉर्डरमैन' का भी विमोचन किया। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अमित शाह ने कहा कि जीवनपर्यन्त कर्तव्य बीएसएफ का सिर्फ घोषवाक्य नहीं है बल्कि आज तक 1900 से अधिक सीमा प्रहरियों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर इस वाक्य को चरितार्थ भी किया है। उन्होंने कहा कि लाखों सीमा प्रहरियों ने अपने जीवन का स्वर्णिम काल कठिनतम परिस्थितियों में परिवार से दूर रहकर बिताया है। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में बीएसएफ ने जिस तरह से देश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा की है, उससे पूरा देश सीमा सुरक्षा बल के इन वीर जवानों पर गर्व करता है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, एक सीमा पर एक ही सुरक्षा बल की तैनाती। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश की सबसे दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल को मिली, जिसे बीएसएफ ने बखूबी निभाया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के बर्फीले इलाके, पूर्वोत्तर के पहाड़, गुजरात और राजस्थान के रेगिस्तान हों, गुजरात का दलदली इलाका हो या फिर सुंदरवन और झारखंड के घने जंगल हों, बीएसएफ ने हमेशा मुस्तैद रहते हुए दुश्मन के नापाक इरादों को विफल किया है। सीमा सुरक्षा बल ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा और वीरता के नए मानांक स्थापित किए हैं। श्री शाह ने कहा कि जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होतीं, वो देश कभी विकसित और समृद्ध नहीं हो सकता।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में सीमाओं पर लगभग 560 किलोमीटर बाड़ लगाकर घुसपैठ और स्मगलिंग पर लगाम कसने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में पूरी पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा को बाड़ लगाकर सुरक्षित कर लिया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि सीमा पर 1100 किलोमीटर क्षेत्र में फ्लडलाइट्स लगाई गई हैं, 542 नए बॉर्डर आउटपोस्ट और 510 ऑब्जरवेशन पोस्ट टावर बनाए गए हैं, पहली बार हरामी नाला क्षेत्र में ऑब्जरवेशन टावर बनाए गए हैं.

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है और ये तभी संभव है जब हमारे वीर जवानों के त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले वीर जवान देश के विकास की नींव हैं। श्री शाह ने कहा कि बीएसएफ के जवानों का जीवन सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ देश के युवाओं को अनुशासन का संदेश भी देता है। उन्होंने कहा कि आज यहां कुल 23 जवानों को बहादुरी पदक दिए गए हैं और 5 जवानों को मरणोपरांत पदक दिए गए हैं। इन 23 में से 11 जवानों को Police Medal For Gallantry, 1 जवान को जीवनरक्षक पदक और 11 जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए गए हैं। श्री शाह ने मरणोपरांत पदक प्राप्त करने वाले 5 शहीदों के परिजनों से कहा कि उनके नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता लेकिन देश की 130 करोड़ जनता इन शहीदों के बलिदान पर हमेशा गर्व करेगी।

उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र सहित अनेक पदक और पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सीमा सुरक्षा को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में सीमाओं की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सुरक्षा, विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया- तीनों को तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों करोड़ रूपये के बजट के साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत की।

- बीएसएफ के जवानों का जीवन सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ देश के युवाओं को अनुशासन का संदेश भी देता है
- जल्द ही भारत वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा
- अगले 2 साल में पूरी पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा को बाड़ लगाकर सुरक्षित कर लिया जाएगा
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की People Inclusive Border Management Policy ने सीमा प्रहरियों के काम के बोझ को बहुत कम किया है
- नारकोटिक्स के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत चल कर बीएसएफ ने नारकोटिक्स के व्यापार पर लगाम कसने का बड़ा काम किया है

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सीमा सुरक्षा को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में सीमाओं की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सुरक्षा, विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया- तीनों को तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों करोड़ रूपये के बजट के साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत की। इसके साथ ही मोदी जी ने सीमावर्ती गांवों में अनेक कल्याणकारी योजनाओं के साथ सीमा सुरक्षा बल और अन्य सभी बलों को जोड़करबल द्वारा सुरक्षा के साथ-साथ जनकल्याण के एक नए कांसेप्ट को भी शुरू किया। श्री शाह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अच्छी रेल, रोड वाटर-वे कनेक्टिविटी और दूरसंचार सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि भू सीमा व्यापार के साथ-साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी बढ़ाया गया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में सीमाओं पर लगभग 560 किलोमीटर बाड़ लगाकर घुसपैठ और स्मगलिंग पर लगाम कसने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में पूरी पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा को बाड़ लगाकर सुरक्षित कर लिया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि सीमा पर 1100 किलोमीटर क्षेत्र में फ्लडलाइट्स लगाई गई हैं, 542 नए बॉर्डर आउटपोस्ट और 510 ऑब्जरवेशन पोस्ट टावर बनाए गए हैं, पहली बार हरामी नाला क्षेत्र में ऑब्जरवेशन टावर बनाए गए हैं, 637 आउटपोस्ट पर बिजली और लगभग 500 स्थानों पर पानी कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की People Inclusive Border Management Policy ने सीमा प्रहरियों के काम के बोझ को बहुत कम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में बीएसएफ ने 30 हज़ार किलोग्राम से ज्यादा नारकोटिक्स पकड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स न केवल देश की भावी पीढ़ी को खोखला करता है बल्कि इससे उत्पन्न पैसा आतंकवाद का वित्त पोषण भी करता है और बॉर्डर पर बने इस ट्रेड लिंक के ज़रिए हथियारों की आवाजाही भी होती है। श्री शाह ने कहा कि इसीलिए इन तीनों कारणों से ये बहुत ज़रूरी है कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नारकोटिक्स के व्यापार के प्रति हमारी कठोर, जीरो टॉलरेंस वाली और संवेदनशील नीति हो और बीएसएफ ने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ ने 2500 से ज्यादा हथियार पकड़े हैं और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी evolving technology के साथ बीएसएफ ने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने अब तक 90 से ज्यादा विदेशी ड्रोन मार गिराए हैं और इसके रूट की पहचान करने के लिए नई दिल्ली में बीएसएफ ड्रोन और साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित कर R&D के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने एरिया डोमिनेशन के लिए फील्ड फॉर्मेशन के साथ 100 ड्रोन उपलब्ध कराए हैं जिसका बहुत अच्छा उपयोग बीएसएफ के जवान कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि 5 साल में 5 करोड़ पौधे लगाने का एक नारा दिया गया था और हमारे Central Armed Police Forces (CAPFs) अब तक 5 करोड़ पौधे लगा चुके हैं और हर पौधे के साथ एक जवान को चिन्हित कर अपने बच्चों की तरह वृक्ष को पालने की व्यवस्था भी बना रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि इन 5 करोड़ पौधों में से 92 लाख पौधे सीमा सुरक्षा बल के सीमा प्रहरियों ने लगाए हैं और आने वाले समय में ये बड़े वृक्ष बनकर इन्हें लगाने वाले जवानों की स्मृति को संजोकर रखेंगे।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं है जब देश वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा और इस दिशा में विगत 10 सालों में मोदी सरकार ने सातत्यपूर्ण प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप हिंसा की घटनाओं में 52 प्रतिशत, मृत्यु की घटनाओं में 70% की कमी आई है और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले 96 से घटकर 45 रह गए हैं। श्री शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद अब सिमटता जा रहा है और अब इस पर एक नए हौंसले और जोश के साथ अंतिम प्रहार करने के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी तैयार है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आने वाले दिनों में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के प्रति कटिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि इन इलाकों में सुरक्षा वैक्यूम को भरने के लिए 2019 से लेकर अब तक 199 नए शिविर खोले गए हैं। श्री शाह ने कहा कि नए कैंप लगाने और गश्त बढ़ने से वामपंथी उग्रवादियों के सभी संसाधनों पर नियंत्रण पाया जा सका है और इसी का परिणाम है कि बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे दुर्गम क्षेत्रों को आज पूरी तरह से वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने में हमें सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि कोल्हान और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभी अंतिम लड़ाई जारी है और यह लड़ाई भी हम ज़रूर जीतेंगे।

तमिलनाडु में बाढ़ से संकट, सनातन बना सहारा

तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सरकार द्रविड़ मॉडल के नाम पर ईसाई धर्म को बढ़ावा देती रही है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 22 दिसंबर 2022 को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि वह और उनकी पत्नी ईसाई हैं और यह सुनकर संघी आग-बबूला हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने उत्तर भारत, सनातन और बीजेपी के प्रति नफरत जाहिर करने के लिए कहा था। जिस सनातन को उदयनिधि ने मच्छर, डेंगू, मलेरिया और न जाने क्या-क्या कहा था और जिस सनातन को खत्म करने की बात कही थी। आज तमिलनाडु जब बाढ़ की तबाही झेल रहा है तब सनातन ही सहारा बन रहा है। खुद को ईसाई कहने वाले स्टालिन के ईसाई मिशनरी कहीं गायब हो गए हैं!उनका काम केवल धर्म परिवर्तन कराना है!4 दिसंबर को मिचौंग तूफान से आई बाढ़ के बाद जमीनी स्तर पर आरएसएस और रामकृष्ण मठ के स्वयंसेवक और भाजपा नेता ही लोगों तक मदद पहुंचाते दिखे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होते गए इसके तीन दिन बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की नींद 7 दिसंबर को खुली उन्होंने भी राहत सामग्री बांटने का एक फोटो सेशन करवा लिया।

तमिलनाडु में बाढ़ से 1.2 करोड़ लोग प्रभावित

बंगाल की खाड़ी से उठे मिचौंग तूफान के कारण आई बाढ़ से तमिलनाडु के 1.2 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई। 4 दिसंबर से सभी स्कूल-कॉलेज बंद हैं। भारतीय वायु सेना के हेलिकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। चेन्नई में एक दिन में सबसे ज्यादा 50 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके चलते आई बाढ़ से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर के कई हिस्सों में तीन दिन से बिजली और इंटरनेट बंद है। लोग परेशान हैं लेकिन स्टालिन सरकार इन लोगों तक मदद पहुंचाने में विफल साबित हुई है।

चेन्नई बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सड़कों पर उतरे सनातनी

तमिलनाडु में 4 दिसंबर को बाढ़ आने के समय से ही रामकृष्ण मठ के स्वयंसेवक के साथ ही अन्य सनातनी चेन्नई बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सड़कों पर हैं। वे दिन-रात लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कहां हैं तमिलनाडु की ईसाई मिशनरियां? वे लोगों की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रही हैं?

रामकृष्ण मठ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाया भोजन

रामकृष्ण मठ केवल चेन्नई में ही बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रही है ऐसा नहीं है। मठ के स्वयंसेवक तमिलनाडु के अन्य बाढ़ प्रवाभित क्षेत्रों में भी लगातार लोगों तक खाना एवं अन्य मदद पहुंचा रही है। श्री रामकृष्ण मठ की चेन्नई शाखा ने 7 दिसंबर 2023 को ट्वीट कर जानकारी दी कि श्री रामकृष्ण मठ, चेन्नई द्वारा 6 दिसंबर 2023 को चक्रवात मिचौंग प्रभावित पट्टिनापक्कम, सेम्मनचेरी और पेरुंबक्कम में राहत कार्य किया गया।

काशी की ज्ञानवापी की तर्ज पर होगा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी ईदगाह मस्जिद का सर्वे

अयोध्या में राम लला मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा की तैयारी अंतिम चरणों में हैं। अगले माह 22 जनवरी को पीएम अयोध्या के धार्मिक समारोह में भाग लेंगे। उधर मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। अब मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे कराने को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने के लिए कहा है। अयोध्या का विवाद भी कई सदियों तक चला था और एएसआई सर्वे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सनातन संस्कृति में अटूट और अगाध श्रद्धा का ही सुफल है कि देशभर में प्राचीनतम मंदिरों के जीर्णोद्धार और मंदिर कॉरिडोर बनाने का काम भी जोरों पर है। बीते दो-तीन साल में सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल मंदिर कॉरिडोर बन चुके हैं। इसके बाद कान्हा का क्रीड़ास्थली ब्रजभूमि की बारी है।

पीएम मोदी देशभर में कर रहे हैं कई प्राचीन धार्मिक स्थलों का कायाकल्प

पीएम मोदी ने कहा कि ब्रज क्षेत्र का विकास आजादी के बाद ही होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि तत्कालीन सरकारों ने इसके बारे में सोचा नहीं। लेकिन अब मथुरा-वृंदावन धाम के कायाकल्प की बारी आ चुकी है। करोड़ों की लागत से वृंदावन में बांके बिहारी कारिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के आराध्य स्थलों, जहां-जहां भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में लीलाएं की हैं, वहां का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी दे दी है।

भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मस्जिद के नीचे मौजूद होने के हैं कई संकेत

अब इस मामले में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने का आदेश दिया है। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी। जिसमें दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर से कराए जाने अनुमति का आधार ये प्रमुख बातें बनीं...

कमिश्नर के जरिए सर्वेक्षण होगा। एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सर्वेक्षण कर सकेंगे. एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और कब से सर्वेक्षण शुरू होगा? इसको लेकर आगे की सुनवाई में तय होगा.

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमारी एप्लीकेशन को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें कोर्ट ने खारिज कर दी है. शाही ईदगाह मस्जिद में ऐसे कई साइन है जो कि दिखाते हैं कि यहां पर हिंदू मंदिर था।

3.अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की मांग करने वाली याचिका स्वीकार करते हुए कहा, "अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। आयोग के तौर तरीकों और प्रारूप को लेकर पक्षकारों के वकीलों को सुना जाएगा।" कोर्ट ने कहा, "यह भी निर्देश दिया जा सकता है कि किसी भी तरीके से ढांचे को कोई नुकसान ना पहुंचे। आयोग उस संपत्ति की वास्तविक स्थिति के आधार पर अपनी निष्पक्ष रिपोर्ट सौंपने को बाध्य है। वादी और प्रतिवादी के प्रतिनिधि अधिवक्ताओं के पैनल के साथ रहकर उनकी मदद कर सकते हैं जिससे जगह की सही स्थिति इस अदालत के समक्ष लाई जा सके।"

देश की जैव-अर्थव्यवस्था की छलांग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का संतुलित और तीव्र विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही अर्थशास्त्रियों और वित्तीय संस्थाओं ने दावा किया है कि भारत 2028 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र शानदार प्रदर्शन कर रहा है। इसमें देश की जैव-अर्थव्यवस्था भी शामिल है, जिसने कमाल कर दिया है। यह अर्थव्यवस्था पिछले आठ साल में 10 अरब डॉलर से आठ गुना बढ़ कर 80 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। 2030 तक इसको 300 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्री-वाइब्रेंट गुजरात सेमिनार-2024 में 'जैव प्रौद्यगिकी : विकसित भारत के लिए नवाचार और कल्याण मार्ग' विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि पिछले आठ साल में भारतीय जैव अर्थव्यवस्था आठ गुना बढ़कर 80 अरब डॉलर हो गई, जो पहले 10 अरब डॉलर थी। भारत ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को 2025 तक 150 अरब डॉलर और 2030 तक 300 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि देश के जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 760 से अधिक कंपनियां और 4,240 स्टार्ट-अप काम कर रहे हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि देश जैव प्रौद्योगिकी वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष 10 में शामिल होने से बहुत दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य उपचार से आगे निकलकर कृषि, पर्यावरण, औद्योगिक उत्पादन और ऐसे कई क्षेत्रों में जटिल सवालों को हल करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था जैव-प्रौद्योगिकी आधारित हो जाएगी। जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर देकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष 3 और दुनिया में जौव-प्रौद्योगिकी के टॉप 12 डेस्टिनेशन्स में से एक है। वैश्विक जौव-प्रौद्योगिकी उद्योग में भारत की लगभग 3 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके अलावा भारत में यूएस के बाहर यूएसएफडीए द्वारा अनुमोदित विनिर्माण संयंत्रों की दूसरी बड़ी संख्या है। कोरोना महामारी के दौरान भारत के जौव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने दिखाया है कि भारत सबसे आगे बढ़कर वैश्विक चुनौतियों से लड़ सकता है और दुनिया की भी मदद कर सकता है। आज भारत डीपीटी, बीसीजी और खसरे के टीके की आपूर्ति में ग्लोबल लीडर है और कोविड के टीके के लिए भी आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन किया और कई देशों की मदद भी की है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 दिसंबर को फिनटेक से संबंधित ग्लोबल थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म-इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को संबोधित किया। इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का विषय 'गिफ्ट-आईएफएससी: नर्व सेंटर फॉर न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज' है। फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया की उम्मीदें भारत पर टिकी हुई हैं। उन्होंने कहा, 'आज पूरी दुनिया भारत से उम्मीदें लगाए हुए है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये, भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और पिछले 10 वर्षों में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों का रिफ्लेक्शन है। इन सुधारों ने देश के आर्थिक बुनियाद को सशक्त किया है।'

Five Individual Centuries In 2023

India enjoyed a comparatively successful T20I season, as they registered their personal best, five individual centuries in 2023, which is one more than their previous best of four in 2023.

5- Surya Kumar Yadav- 100 vs South Africa

On December 14, 2023, in the last T20I match of the year for team India, they needed to register a win against the Proteas in the last match of the series to draw the series.

4 - Yashasvi Jaiswal- 100 vs Nepal

Yashasvi Jaiswal

The Indian cricket team was playing their first ever Asian Games match, in the quarterfinal 1 match against Nepal in the 2023 Hangzhou Asian Games.

Indian skipper Ruturaj Gaikwad won the toss and opted to bat first, and on a surface where all the other batsmen found it hard to hit big shots, Yashasvi Jaiswal took on the charge of the onslaught on his shoulders and registered a hard-hitting century to take his team to a strong total.

Yashasvi scored 100 runs in just 49 deliveries, with the help of eight boundaries and seven sixes.

India went on to win the match and the tournament to lift their first gold medal in the event.

3- Surya Kumar Yadav 112* vs Sri Lanka

Surya Kumar Yadav

On January 7, 2023, the men in blue were up against the Sri Lankan Lions in the third T20I match of the series, with the fate of the series on the line. The series was level at 1-1, after two matches, and the winner of the third and final match would also win the series.

Indian skipper Hardik Pandya won the toss and opted to bat first.

India vs Sri Lanka 3rd T20 highlights in Rajkot #india #srilanka # highlight thanks for watchin1.9k

2. Ruturaj Gaikwad 123* vs Australia

Asian Games - Ruturaj Gaikwad

India was playing Australia in a five-match T20I series, and as they had lost the ICC World Cup 2023 finals to the same team, and emotions were running pretty high.

India, who had already won the first two matches of the series, were aiming to win the third match and seal the series with a win.

Australian skipper Mathew Wade won the toss and invited the men in blue to bat first.

Ruturaj Gaikwad Century VS Australia || 123 runs in 57 balls || IND vs AUS 3rd T20I

1. Shubman Gill- 126* vs New Zealand

shubman gill 3rd ODI tonshubman gill 3rd ODI ton

On February 1, India was taking on the New Zealand team with the three-match series level at 1-1, after two matches.

India, while batting first, lost their first wicket with just seven runs on board, but the other opener, Shubman Gill, went on to score a not-out 126 runs innings, with the help of 12 boundaries and seven sixes.

Shubman Gill 126* Runs Of 63 Balls | India Vs New Zealand 3rd T20 Highlights 1st February 2023 Shubman's 126* is also the highest individual score in T20I for the men in blue.

Lok Shakti

N A T I O N A L I S M
O P E N I O N
R E M A R K
D I S C O V E R Y
E N L I G H T E N
A N A L Y S I S
K N O W L E D G E
P O L I T I C S
I D E O L O G Y

Access Lok Shakti online for free.

**Now, read Lok Shakti on your smart phone instantly.
Point your phone's scanner on the
code and align it in the frame.
You will be guided instantly to www.lokshakti.in.**

All Rights Reserved
Terms & Conditions Apply.
Lok Shakti exclusively holds all the rights to cancel the subscription without any prior Notice.
If you wish to Unsubscribe, let us know at the official contact no.
In case of any Dispute, Jurisdiction area will be Raipur

Owner, Printer, Publisher & Editor- Premendra Agrawal, Published from 5/756, Desh Bandhu Press Road, Behind Sindhi School, Raipur (C.G.) - 492001
& Printed at Commercial Services, Ramsagarpara, Raipur (C.G.)